website: www.royalpatrika.com
G-mail: royalpatrika@gmail.com
Yahoo: royal_patrika@yahoo.com

R.N.I. No. RAJHIN/2012/48736

दैनिक

रॉयल पत्रिका

वर्ष : 13 | अंक : 305 | पेज: 8 | जयपुर, रविवार 12 अक्टूबर 2025 | मूल्य: 1.50 रुपये

पीएम मोदी ने क्वालकॉम सीईओ से AI और नवाचार में भारत की प्रगति पर चर्चा की

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका स्थित चिप दिग्गज क्वालकॉम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) क्रिस्टियानो आर. अमोन से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन और कौशल में भारत की प्रगति पर चर्चा की।

पीएम मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर और एआई मिशनों के प्रति क्वालकॉम की प्रतिबद्धता की सराहना की

पीएम मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर और एआई मिशनों के प्रति क्वालकॉम की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ऐसी तकनीकों के निर्माण के लिए खास प्रतिभा और पैमाने प्रदान करता है, जो सामूहिक भविष्य को आकार देंगी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्रिस्टियानो के एक पोस्ट को रिपोस्ट कर लिखा, "क्रिस्टियानो आर. अमोन से मुलाकात बेहद खास और अच्छी रही। हमने एआई, इनोवेशन और स्किलिंग को लेकर भारत की प्रगति पर चर्चा की।"

भारत के सेमीकंडक्टर और एआई मिशनों को लेकर क्वालकॉम के कमिटमेंट को देखकर खुशी हुई

उन्होंने आगे कहा, "भारत के सेमीकंडक्टर और एआई मिशनों को लेकर क्वालकॉम के कमिटमेंट को देखकर खुशी हुई। देश ऐसी तकनीकों के निर्माण के लिए अनमैच्ड टैलेंट और पैमाने प्रदान करता है, जो कलेक्टिव फ्यूचर को आकार देंगी।" इससे पहले क्रिस्टियानो ने अपने एक्स पोस्ट पर क्वालकॉम और भारत के बीच पार्टनरशिप को लेकर उत्पादक बातचीत के लिए पीएम मोदी का आभार जताया।

इंडिया एआई और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन साथ-साथ 6जी में बदलाव के लिए शानदार बातचीत हुई

उन्होंने बताया कि इंडिया एआई और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन साथ-साथ 6जी में बदलाव के लिए शानदार बातचीत हुई। उन्होंने एक्स पर लिखा, "हम एआई स्मार्टफोन, पीसी, स्मार्ट ग्लास, ऑटो, इंडस्ट्रियल और अन्य क्षेत्रों में एक भारतीय इकोसिस्टम को डेवलप करने के अवसरों से उत्साहित हैं।" इससे पहले क्वालकॉम इंडिया ने जानकारी देते हुए बताया था कि कंपनी भारत के डिजिटल भविष्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रही है।

क्वालकॉम ने IMC 2025 में AI, 6G और स्मार्ट टेक्नोलॉजी से भारत के डिजिटल परिवर्तन में योगदान का प्रदर्शन किया

साथ ही, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी तकनीकी समाधानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दे रही है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 में क्वालकॉम ने एज एआई और 6जी से लेकर स्मार्ट होम, कनेक्टेड डिवाइस और एडवांस कंप्यूटर प्लेटफॉर्म तक अलग-अलग तरह के इनोवेशन को पेश किया। साथ ही बताया गया कि कंपनी की तकनीक भारत के डिजिटल परिवर्तन को किस प्रकार गति देने का काम करेंगी। क्वालकॉम भारत की तकनीकी यात्रा में लंबे समय से भागीदार रहा है। कंपनी ने देश को 3जी से 5जी तक सहयोग दिया है, साथ ही अर्ली-स्टेज रिसर्च, रणनीतिक साझेदारियों और लोकल आरएंडडी निवेशों के माध्यम से 6जी के लिए सक्रिय रूप से तैयारी भी की है।

अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर तेज़: जिनपिंग के एक्सपोर्ट कंट्रोल के जवाब में ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाया

अमेरिका (एजेंसी)। अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर से ट्रेड वॉर छिड़ता नजर आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन से काफी नाराज हैं। उन्होंने चीन के ऊपर 100 फीसदी टैरिफ लगाया है। दरअसल, चीन ने अपने प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लागू करने का ऐलान किया है। चीन की इसी घोषणा से अमेरिकी राष्ट्रपति भड़क उठे।

पत्र के अनुसार, चीन 1 नवंबर 2025 से अधिकांश उत्पादों, यहां तक कि कुछ गैर-निर्मित वस्तुओं पर भी बड़े पैमाने पर निर्यात नियंत्रण लागू करेगा

ट्रूथ पर पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, "अभी-अभी पता चला है कि चीन ने व्यापार के मामले में बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए दुनिया को एक पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि वे 1 नवंबर, 2025 से अपने लगभग हर उत्पाद पर, यहां तक कि कुछ उत्पादों पर जो उनके द्वारा बनाए भी नहीं गए हैं, बड़े पैमाने पर निर्यात नियंत्रण लागू करेंगे। इसका असर सभी देशों पर पड़ेगा और जाहिर है कि यह योजना उन्होंने सालों पहले ही बना ली थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है और दूसरे देशों के साथ व्यवहार करना एक नैतिक अपमान है।"

अमेरिका चीन पर मौजूदा शुल्क के अलावा 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा और 1 नवंबर से सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर निर्यात नियंत्रण लागू करेगा

चीन पर 100 फीसदी अन्य टैरिफ लगाने का ऐलान करते हुए उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा, जो वर्तमान में चीन द्वारा चुकाए जा रहे किसी भी टैरिफ के अतिरिक्त होगा। इसके अलावा, 1

नवंबर से, हम सभी महत्वपूर्ण सॉफ़्टवेयर पर निर्यात नियंत्रण लगा देंगे। यह विश्वास करना असंभव है कि चीन ने ऐसा कोई कदम उठाया होगा, लेकिन उन्होंने उठाया है, और बाकी सब इतिहास है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!

अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर 100% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की, कहा रेयर अर्थ्स निर्यात नियंत्रण से वैश्विक बाजार प्रभावित होंगे

बता दें, चीन पर पहले से 30 फीसदी टैरिफ लागू है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने 100 फीसदी अलग से टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, "चीन में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं! वे बहुत आक्रामक हो रहे हैं और दुनिया भर के देशों को पत्र भेज रहे हैं कि वे रेयर अर्थ्स से जुड़े हर उत्पादन तत्व पर निर्यात नियंत्रण लगाना चाहते हैं, भले ही वह चीन में निर्मित न हो। किसी ने भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन असल में, इससे बाजार "अवरुद्ध" हो जाएंगे और दुनिया के लगभग हर देश, खासकर चीन, का जीना मुश्किल हो जाएगा। हमसे कुछ अन्य देशों ने संपर्क किया है जो इस व्यापारिक दुश्मनी से बेहद नाराज हैं, जो अचानक शुरू हुई है।"

अमेरिका के पास भी एकाधिकार की स्थिति है, जो चीन की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और दूरगामी है

उन्होंने कहा, "पिछले छह महीनों में चीन के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, जिससे व्यापार के मामले में यह कदम और भी आश्चर्यजनक हो गया है। मुझे हमेशा लगता था कि वे घात लगाए बैठे हैं, और अब, हमेशा की तरह, मैं सही साबित हुआ! ऐसा कोई तरीका नहीं है कि चीन को दुनिया को "बंदी" बनाने की अनुमति दी जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि यह उनकी काफी समय से योजना थी। यह एक भयावह और शत्रुतापूर्ण कदम है। लेकिन अमेरिका के पास भी एकाधिकार की स्थिति है, जो चीन की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और दूरगामी है।"

ट्रंप ने कहा, चीन का पत्र असामान्य है और शी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ी, एपीईसी समिट में ट्रंप-जिनपिंग की संभावित मुलाकात अब अनिश्चित है

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि चीन ने जो पत्र भेजा है वह कई पृष्ठों का है। जो चीजें पहले नियमित थीं, वे अब बिल्कुल भी नियमित नहीं रहीं। मैंने राष्ट्रपति शी से बात नहीं की है क्योंकि ऐसा करने का कोई कारण नहीं था।बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एपीईसी समिट में शामिल होने के लिए दक्षिण कोरिया जाने वाले थे। इस समिट के दौरान राष्ट्रपति जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात होनी थी। हालांकि, अब यह मुलाकात अनिश्चित है।

बिहार विधानसभा चुनाव: पहले चरण की सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी

- 17 अक्टूबर तक भरे जाएंगे नामांकन

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत आज शुक्रवार से पहले चरण के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह नोटिफिकेशन बिहार राज्यपाल की ओर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15(2) के तहत जारी किया गया है। बिहार के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित करने के लिए यह अधिसूचना महत्वपूर्ण है।

पहले चरण के लिए नामांकन करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर

भारत निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के लिए नामांकन करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर (शुक्रवार) निर्धारित की है। 18 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी। अभ्यर्थियों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर रखी गई है।

नामांकन केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के विशेष निर्देश

चुनाव आयोग ने नामांकन केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के विशेष निर्देश दिए हैं। नामांकन के समय प्रत्यायशी के साथ सिर्फ तीन वाहन और प्रस्तावक समेत अधिकतम 5 व्यक्ति ही जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि पूरी नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी।

निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए राज्यभर में लगभग 8.50 लाख अधिकारियों की तैनाती की है। आयोग के अनुसार, इन अधिकारियों में 4.53 लाख मतदान कर्मी, 2.50 लाख पुलिसकर्मी, 28,000 से अधिक मतगणना कर्मी, और 18,000 माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल हैं।

बिहार में पहली बार सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में सामान्य पर्यवेक्षक तैनात किए गए

इस बार बिहार में पहली बार सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में सामान्य पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके अलावा, चुनाव पर निगरानी रखने के लिए 38 पुलिस पर्यवेक्षक और 67 व्यय पर्यवेक्षक की भी नियुक्ति की गई है। ये पर्यवेक्षक संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से नियमित संवाद कर चुनाव प्रक्रिया में किसी भी समस्या का समाधान सुनिश्चित करेंगे।

121 विधानसभा सीटों के पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को

पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों के लिए 6 नवंबर (गुरुवार) को वोट डाले जाएंगे। उस सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण में पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर जिले की विधानसभा सीटें शामिल हैं। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और उसके बाद मतगणना 14 नवंबर को होगी।

दीपावली से पहले कारोबारियों को दिल्ली सरकार का तोहफा

-694 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड जारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। दीपावली से पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी के कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार ने इस वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 694 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड जारी किया है, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि छोटे-बड़े सभी व्यापारियों को तय समय सीमा में जीएसटी रिफंड देने के लिए उनकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रेरित होकर 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' की नीति पर गंभीरता से कार्य कर रही है। सरकार बड़े बाजारों के पुनर्विकास की योजनाओं पर काम कर रही है और व्यापारियों की समस्याओं को हल करने के लिए दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि जब व्यापारियों को कारोबार चलाने में आसानी होगी, तभी विकसित दिल्ली का सपना पूरा होगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली सरकारों ने जीएसटी रिफंड प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया था, जिससे लंबित रिफंड बढ़ते गए। लेकिन उनकी सरकार ने इसे प्राथमिकता दी और आईआईटी-हैदराबाद के सहयोग से एक उन्नत आईटी मॉड्यूल विकसित किया है। यह मॉड्यूल डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन और तेज जांच प्रक्रिया पर आधारित है, जिससे रिफंड आवेदन तेजी से निपटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने

इस वित्त वर्ष में अप्रैल से अब तक 7375 रिफंड आवेदनों का निपटारा कर 694 करोड़ रुपये की राशि व्यापारियों के खातों में जमा कर दी है। इसके साथ ही सितंबर माह में अकेले 227 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा मासिक रिफंड रिकॉर्ड है।

मुख्यमंत्री ने जीएसटी विभाग और कर अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि समय पर रिफंड से व्यापारिक संस्थाओं में विश्वास बढ़ता है और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को तेजी से काम करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्विवादित और वास्तविक रिफंड आवेदनों का निपटारा जल्द किया जाए ताकि दीपावली तक अधिकतम कारोबारियों को रिफंड मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि समयबद्ध रिफंड से व्यापारियों को पूंजी की उपलब्धता बढ़ेगी, मुकदमेबाजी का तनाव घटेगा और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार व्यापारिक नियमों को सरल कर रही है और अनावश्यक बाधाओं को दूर कर रही है।

त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार का एयरलाइनों को निर्देश

-सुरक्षा प्रोटोकॉल सख्ती के साथ ही हवाई किराया उचित रखने की सलाह

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने घरेलू एयरलाइनों से सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने को कहा। साथ ही एयरलाइनों से यात्री सुविधा और सेवा गुणवत्ता में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का आग्रह किया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घरेलू एयरलाइनों के साथ मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उनके परिचालन और तकनीकी प्रदर्शन का आकलन किया गया। बैठक में उन्होंने सुरक्षा और यात्री सुविधा पर विशेष ध्यान दिया।

अधिकांश एयरलाइनों, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, अकासा एयर, अलायंस एयर, फ्लाई91, फ्लाईबिग और इंडियावन एयर, ने इसमें भाग लिया। सभी ने सुरक्षा घटनाओं और यात्री शिकायतों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट सहित अपने प्रदर्शन के आंकड़े प्रस्तुत किए। सुरक्षा निरीक्षण, बेड़ा प्रबंधन और यात्री-केंद्रित पहलों पर व्यापक चर्चा हुई। प्रत्येक एयरलाइन के साथ उनके संचालन में आने वाली बाधाओं की पहचान करने और उनकी चुनौतियों का समाधान करने पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक के दौरान, केंद्रीय मंत्री नायडू ने एयरलाइनों को आगामी त्योहारी सीजन के दौरान सभी क्षेत्रों में हवाई किराए को उचित बनाए रखने के लिए भी जागरूक किया।एयरलाइनों ने आश्वासन दिया कि यात्री सुविधा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी और बताया कि त्योहारी मांग को पूरा करने के लिए उच्च यातायात वाले मार्गों पर अतिरिक्त उड़ान क्षमताएं तैनात की गई हैं। मंत्री ने डीजीसीए की टैरिफ निगरानी इकाई को हवाई किरायों पर कड़ी निगरानी रखने और एयरलाइनों द्वारा घोषित टैरिफ रेंज का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। बातचीत के दौरान, उन्होंने एयरलाइनों द्वारा किए गए शिकायत निवारण की भी समीक्षा की और उन्हें समय पर यात्री शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से समाधान करने का निर्देश दिया। मंत्रालय के यात्री शिकायत निवारण पोर्टल, एयरसेवा को भी उन्नत किया गया है ताकि यात्री उच्च हवाई किरायों से संबंधित शिकायतें भी दर्ज कर सकें।उन्होंने एयरलाइनों को अपने संचालन, प्रथाओं और सेवा वितरण में प्रधानमंत्री के स्वच्छता के दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।उन्होंने उन्नत तकनीकों और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार प्रथाओं को अपनाकर भारतीय विमानन को और अधिक टिकाऊ बनाने में एयरलाइ नों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की।

भारत और ब्रिटेन ने रक्षा सहयोग को नई दिशा दी

- मुंबई में हुई बैठक में इंडो-पैसिफिक साझेदारी पर जोर

नई दिल्ली (एजेंसी)। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शुक्रवार को मुंबई में ब्रिटेन के रक्षा राज्य मंत्री वर्नन कोकर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। यह बैठक भारत में ब्रिटेन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप (सीएसजी) की यात्रा के दौरान आयोजित की गई। बैठक में दोनों देशों ने मौजूदा रक्षा सहयोग की समीक्षा और भविष्य में रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई। संजय सेठ ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि ब्रिटेन का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जिसकी अगुवाई प्रिंस ऑफ वेल्स कर रहे हैं, ने भारतीय नौसेना के साथ पश्चिमी तट पर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 'कोकण-25' के समुद्री चरण को सफलतापूर्वक

पूरा कर लिया है। वर्तमान में यह समूह मुंबई और गोवा में हार्बर चरण की गतिविधियों में भाग ले रहा है।

संजय सेठ ने कहा कि इस तरह के संचालनिक अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच परिचालन समझ और सामरिक सहयोग को गहरा करते हैं। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भारत की स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमताओं तथा 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत विकसित हो रही प्रणालियों पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत और ब्रिटेन ने वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग और नए अवसरों को बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने हिंद-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर भी सहमति जताई ताकि मुक्त, खुला और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके, जिसमें नौवहन की स्वतंत्रता बनी रहे।

दोनों देशों ने यह भी दोहराया कि वे एक मजबूत, बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभकारी रक्षा साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो भारत-यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी और भारत-यूके विजन 2035 के तहत आगे बढ़ाई जा रही है। यह विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2025 में ब्रिटेन यात्रा के दौरान अपनाया गया था।

कफ सिरप केस: दवा दुकानों की चेकिंग करने उतरे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री

-300 से ज्यादा सैंपल जांच को भेजे

नई दिल्ली (एजेंसी)। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत होने और तीन-तीन कफ सिरप को बैन करने के मामले को लेकर के झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सड़कों पर शुक्रवार को उतरे और दवा दुकानों में जाकर कफ सिरप की जांच की। इससे साथ ही इरफान अंसारी सदर अस्पताल में पैरासिटामोल की गोली में फंगस लगने के मामले के लिए भी जांच के लिए भी सदर अस्पताल पहुंचे और वहां इसकी जांच की। जांच के बाद इरफान अंसारी ने बताया कि दवा दुकानों में से कई कफ सिरप के सैंपल कलेक्शन करके जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजे गए हैं।

300 से ज्यादा सैंपल को जांच के लिए भेजा गया

उन्होंने बताया कि तकरीबन 300 से ज्यादा सैंपल को अब तक झारखंड से लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा गया है, ताकि मध्य प्रदेश

और राजस्थान में जिस तरह से बच्चों की मौतें हुई हैं, उसे रोका जा सके। वहीं, उन्होंने सदर अस्पताल में पैरासिटामोल फंगस लगी हुई दवा के मामले की भी जांच की। उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य विभाग को बदनाम करने के लिए एक साजिश है। मैंने खुद जाकर के पैरासिटामोल दवाई की जांच की है। कहीं किसी प्रकार का कोई फंगस नहीं लगा हुआ है।

पैरासिटामोल में फंगस पाए

उन्होंने कहा कि आज के अखबारों में पैरासिटामोल में फंगस पाए जाने की बात सामने आई है। मैं खुद इसे देखने आया था और दवा मेरे पास है। दवा लेने पर वह पारदर्शी होती है। दवा ठीक से दी गई थी। मैंने सीसीटीवी कैमरे से पुष्टि की कि दवा ठीक है। दवा लेने के बाद फंगस कैसे दिखाई दिया, यह स्पष्ट नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट अदालत की निगरानी में जांच की मांग

उधर, कफ सिरप पीने से बच्चों की हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। याचिका में इस गंभीर मामले की जांच राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या सीबीआई के माध्यम से विशेषज्ञों की समिति बनाकर कराए जाने की मांग की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने सुनवाई 10 अक्टूबर के लिए निर्धारित की।

रॉयल पत्रिका

संपादकीय....

कर्नाटक की मासिक धर्म अवकाश नीति: कार्यस्थल पर संवेदना और समानता की नई पहल

कर्नाटक की मासिक धर्म अवकाश नीति महिलाओं के सम्मान और संवेदना की दिशा में एक अहम पहल है। महिलाओं के जीवन में मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसके दौरान उन्हें शारीरिक असुविधा, दर्द, कमजोरी और मानसिक थकान का सामना करना पड़ता है। लंबे समय तक इस विषय पर खुलकर चर्चा नहीं की गई, क्योंकि समाज में इसे एक प्रकार का वर्जित विषय माना गया। परंतु आज जब महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, तब यह आवश्यक है कि उनके स्वास्थ्य और जैविक जरूरतों को भी नीति निर्माण में उचित स्थान दिया जाए। कर्नाटक सरकार की 'मासिक धर्म अवकाश नीति-2025' इसी सोच को आगे बढ़ाती है। इस नीति के तहत कामकाजी महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म के दौरान तीन दिन का वैकल्पिक अवकाश देने का प्रावधान किया गया है। यह न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील सोच को दर्शाता है, बल्कि कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता और मानवीय दृष्टिकोण को भी प्रोत्साहित करता है। यह नीति महिलाओं को यह भरोसा देती है कि वे अपने स्वास्थ्य को लेकर खुलकर बात कर सकती हैं और बिना झिझक आवश्यक आराम प्राप्त कर सकती हैं। हमारे देश में बड़ी संख्या में महिलाएं अब विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं—चाहे शिक्षा हो, उद्योग, सेवा क्षेत्र, राजनीति या प्रशासन। ऐसे में उनकी जैविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुविधाएं देना केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में वास्तविक कदम है। अक्सर कार्यस्थलों पर महिलाएं मासिक धर्म के दिनों में भी मजबूरी में काम करती हैं, जिससे उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इस नीति से न केवल उन्हें राहत मिलेगी बल्कि उनकी कार्यक्षमता और उत्पादकता में भी सुधार होगा। इसके साथ यह समझना भी ज़रूरी है कि ऐसी नीतियां केवल सरकारी दफ्तरों या सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित न रहें, बल्कि निजी क्षेत्र में भी लागू की जाएं। क्योंकि आज की बड़ी संख्या में महिलाएं निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों, शैक्षणिक संस्थानों और सेवा क्षेत्रों में काम कर रही हैं। कर्नाटक का यह कदम पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है, अगर अन्य राज्य सरकारें और निजी संस्थान भी इसी दिशा में पहल करें। महिलाओं की कार्यस्थल संबंधी अन्य जरूरतों पर भी ध्यान देना समय की मांग है। कार्यस्थल तक आने-जाने की सुरक्षित व्यवस्था, बच्चों के लिए डे-केयर या क्रेच सुविधा, और लचीले कार्य घंटे जैसी व्यवस्थाएं महिलाओं के जीवन को संतुलित बनाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। महिलाओं के लिए अनुकूल कार्य संस्कृति तैयार करना केवल सहानुभूति का मामला नहीं, बल्कि यह देश की आर्थिक प्रगति से जुड़ा हुआ विषय है।

गाजा में शांति की नई पटकथा: ट्रंप की बीस सूत्री योजना या पश्चिम एशिया की राजनीति का एक नया भ्रम?

-दो साल की जंग के बाद गाजा में ट्रंप की बीस सूत्री शांति योजना से उम्मीदें जगीं, मगर नेतन्याहू और हमास की शर्तें बनी रुकावट

हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नया प्रस्ताव पेश किया — अक्सर "20-सूत्री योजना" के नाम से संदर्भित — जिसके तहत गाजा युद्ध समाप्ति, बंधकों का विमोचन, गाजा के पुनर्विकास, हमास के सशस्त्र नियंत्रण को समाप्त करने आदि बात की गई है

मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

हमास तथा अन्य सशस्त्र संगठन गाजा की राजनीतिक/प्रशासनिक व्यवस्था से अलग होंगे; गवर्नेंस एक 'तकनीकी, गैर-राजनीतिक (technocratic)' समिति के द्वारा होगी। "Board of Peace" नामक एक अंतरराष्ट्रीय संरचना बनेगी, जिसमें ट्रंप अध्यक्ष होंगे, साथ ही अन्य अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय हस्तियाँ शामिल होंगी, और इस बोर्ड के अधीन गाजा का पुनर्विकास और शांति की प्रत्याशाएँ निर्धारित होंगी। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था सुधारों और निगरानी व्यवस्था के अंतर्गत, हमास को हथियार छोड़ने या कम-से-कम उनकी क्षमताओं को सीमित/निरस्त करने की शर्त रखी गई है। इजरायल सैनिकों को गाजा से पीछे हटना होगा, बंधकों की रिहाई होगी। बदले में हमास को कुछ हल्की उम्मीदों के साथ योजना पर विचार करने के लिए समय दिया गया। गाजा के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक पैकेज, बुनियादी सुविधाएं, विशेष आर्थिक क्षेत्र आदि शामिल हैं। फिलिस्तीनी प्राधिकरण (Palestinian Authority) को सुधारात्मक उपक्रमों के बाद गवर्नेंस सौंपने की बात कही गई है।

नेतन्याहू का रुख — फिलिस्तीनी राष्ट्रता स्वीकार करना

नेतन्याहू लंबे समय से सार्वजनिक रूप से यह दावा कर चुके हैं कि "एक फिलिस्तीन राज्य" (a Palestinian state) का कोई निर्माण नहीं होगा, खासकर यदि वह पश्चिमी तट या गाजा के नियंत्रित हिस्सों में हो, जैसा कि बहुत से प्रस्तावों में वर्णित है।

कुछ प्रमुख बिंदु:

हाल ही में उसने कहा है कि पश्चिमी तट में नए इजरायली बस्तियों के विस्तार (settlement expansion), विशेष रूप से "E1" योजना, इस राज्य-निर्माण को लगभग असंभव बना देता है। उसने उन देशों के सरकारी कदमों का भी विरोध किया है जो फिलिस्तीनी राज्य को एकरूपता से मान्यता दे रहे हैं (UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि), उन राज्यों की इस तरह की मान्यता को "पुरस्कार आतंकवाद को देना" जैसा बयान दिया है। संसद और कैबिनेट के स्तर पर भी नेतन्याहू ने "एक-तरफ़ा" (unilateral) फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को अस्वीकार किया है, माना कि ऐसा करना इज़राइल-फिलिस्तीन संवाद और शांति प्रक्रिया के लिए हानिकारक या खतरनाक होगा। इसका मतलब है कि नेतन्याहू फिलिस्तीनी राष्ट्रता (statehood) को एक स्वायत्त, संप्रभु राज्य के रूप में स्वीकार करने के प्रति बहुत संशयवादी और डरावने हैं। उनके लिए "सुरक्षा नियंत्रण", "आतंकवादी भड़काने वालों से दूरी", और "इज़राइल की सुरक्षा" सर्वोपरि हैं।

हमास की स्थिति: स्वीकार्यता, किन्तु परन्तु, और चुनौतियाँ

हमास की मानसिकता, उसके राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य लक्ष्यों की जटिलता, और उसका क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय समर्थन इसके निर्णय क्षमताओं को प्रभावित करता है।

स्वायत्तता और नियंत्रण की अवधारणा

हमास यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि गाजा की जनता का प्रतिनिधित्व और नियंत्रण उनके हाथ में कम-से-कम कुछ बचा हो — विशेष रूप से सुरक्षा, हथियारों का नियंत्रण, स्थानीय प्रशासन आदि पर। प्रस्ताव में कहा गया है कि हमास को पूरी तरह से शासन से अलग कर दिया जाए (governance से), लेकिन कामचलाऊ प्रशासन तकनीकी समिति को सौंपा जाए। यह हमास के लिए स्वीकार्य हो सकता है यदि ऐसी व्यवस्थाएँ स्थानीय हितों की रक्षा करें, लेकिन पूर्ण नियंत्रण के त्याग के साथ यह बड़ा त्याग होगा।

हथियार, सुरक्षाम्न व्यवस्था और हथियार त्याग

हमास के लिए यह बहुत कठिन शर्त है कि वह हथियार त्यागे या कम से कम उनका नियंत्रण खोए। हथियार उसके लिए न सिर्फ लड़ाई का साधन हैं बल्कि राजनीतिक शक्ति और वैचारिक अस्तित्व का भी प्रतीक। अंतरराष्ट्रीय निगरानी, हथियारों का निरस्त्रीकरण, सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी आदि पर हमास को भरोसा होना चाहिए कि उसके विरोधियों द्वारा धोखा नहीं होगा।

बंधकों की रिहाई और जीवन रक्षा

बंधकों की रिहाई हमास की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि इस तरह के प्रस्तावों में इसे एक मुख्य बिंदु माना गया है। यदि योजना में यह स्पष्ट है कि बंधकों की रिहाई बिना अतिरिक्त शर्तों के होगी, तो यह हमास को स्वीकार करने की ओर प्रेरित कर सकता है। लेकिन यदि रिहाई की शर्तें बहुत कठोर हों, या कुछ बंधक सुरक्षित रूप से वापस न हों, तो इस पर हमास विरोध कर सकता है।

भविष्य की राजनीतिक स्थिति

हमास को यह देखना होगा कि इस योजना के बाद उसकी भूमिका क्या होगी, और क्या गाजा की जनता नेतृत्व या प्रतिनिधित्व में हमास को पूरी तरह से बाहर कर देने से राजनीतिक अस्थिरता, विरोध या संघर्ष जन्म लेगा। जनता के बीच हमास की जन-स्वीकृति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय दबाव

हमास पर क्षेत्रीय दबाव है — अन्य अरब देशों, मुस्लिम देशों और मध्यस्थों (जैसे कतर, मिस्र, तुर्की) के माध्यम से — कि वह शांति की इस पहल में भाग ले। लेकिन इसी तरह उनके लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वे ऐसी शर्तों को स्वीकार न करें जो उन्हें "घुटने टेकने" जैसा लगे।

क्या हमास स्वीकार कर सकेगा? संभावनाएँ और बाधाएँ

"हां" और "ना" दोनों के तत्व मिलते हैं। यहाँ विश्लेषण है: संभावनाएँ (हां की ओर झुकाव)

पनाह और विनाश की स्थिति

गाजा के निवासियों पर लंबे समय से जारी युद्ध, बमबारी, बुनियादी सुविधाएँ ध्वस्त होना, मानवीय संकट आदि ने हमास पर दबाव बढ़ा दिया है कि कोई रास्ता निकले। यदि यह योजना बुनियादी ज़रूरतों (भोजन, पानी, अस्पताल) को तुरंत बहाल करे, तो जनता में समर्थन हो सकता है, जिससे हमास के लिए स्वीकारना आसान हो सकता है।

बंधकों की रिहाई

यदि योजना तुरंत और पूर्णता से बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करे, तो यह हमास की नैतिक और राजनीतिक जीत होगी, जिससे वे राजनैतिक पूँजी अर्जित कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण बाहरी समर्थन

अरब देशों, अन्य मुस्लिम देशों, मध्यस्थों (मिस्र, कतर आदि) द्वारा समर्थन मिलना हमास के लिए सुविधा बढ़ाएगा। यदि अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा यह संभावना कि योजना की शर्तें ईमानदारी से लागू हों, बनाई जाए, तो हमास के लिए स्वीकार करना संभव होगा।

पछि की राजनीतिक व्यवस्था

यदि हमास को यकीन हो कि उनकी राजनीतिक भूमिका पूरी तरह समाप्त नहीं होगी, कि गाजा के लोग तकनीकी समिति या बाद में फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण के रूप से न्याय पाएँगे और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तो वे भाग लेने के लिए अधिक तैयार हो सकते हैं।

चुनाव आयोग बिहार में रोड-शो पर सख्त पाबंदी लगाए

-कितनी मौतों के बाद जागेगी व्यवस्था?

तमिलनाडु के करूर में हाल ही में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई भगदड़ में 41 निर्दोष लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह कोई पहली घटना नहीं है जब भीड़ प्रबंधन की नाकामी और नेताओं की प्रचार हवस ने लोगों की जान ले ली हो। इससे पहले भी विभिन्न राज्यों में रोड-शो, विजय जुलूस या रैलियों के दौरान कई दर्दनाक हादसे हो चुके हैं, लेकिन हर बार सरकारें और चुनाव आयोग "जांच समिति" बनाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तमिल सुपरस्टार विजय के करीबी दोस्त और अभिनेता आधव अर्जुन ने इस घटना पर शोक जताते हुए लिखा कि "दुष्ट शासक के अधीन कानून भी दुष्ट हो जाते हैं।" उन्होंने श्रीलंका और नेपाल की तरह युवाओं से परिवर्तन की अपील की। मगर असल सवाल यह है कि जब सड़कों पर अराजकता फैलाने वाले ही परिवर्तन के दावेदार हों, तो बदलाव की उम्मीद किससे की जाए? यह समय भावनात्मक नारों से आगे बढ़कर ठोस व्यवस्था सुधार का है, और सबसे पहले ज़रूरत है कि चुनाव आयोग रोड-शो और सड़कों पर होने वाली रैलियों पर सख्त पाबंदी लगाए।

इस पूरे मसले को पाँच मुख्य बिंदुओं में समझना ज़रूरी है —

मुद्दे को भटकाने की परंपरा

जब भी किसी रैली या रोड-शो में भगदड़ या जान-माल का नुकसान होता है, सरकार और संबंधित दल जांच समितियों के गठन की घोषणा करके जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। यही हाल बेंगलुरु में आरसीबी के विजय समारोह, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टिकट लाइन की भगदड़, और अब करूर की त्रासदी में देखने को मिला। हर जगह एक ही पैटर्न दोहराया गया — पहले मीडिया कवरेज, फिर राजनीतिक बयानबाज़ी, और अंत में जांच समिति। तमिलनाडु की टीबीके पार्टी की रैलियों में इससे पहले भी तीन लोगों की मौत हो चुकी थी। लेकिन न तो भीड़ प्रबंधन में सुधार हुआ और न ही नेताओं पर कोई ठोस कानूनी कार्रवाई हुई। अब 41 निर्दोषों की मौत के बाद भी "सीबीआई जांच" के नाम पर कानूनी नौटंकी चल रही है। अदालतों में मुकदमों का अंबार बढ़ता जा रहा है और जनता

के पैसे से चलने वाली सरकारी मशीनरी बेवजह के कानूनी झंझटों में उलझी है। सवाल है — जब एनडीएमए (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) और बीपीआरडी (ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट) ने पहले ही 2020 और 2025 में भीड़ नियंत्रण और कार्यक्रम प्रबंधन के स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं, तो फिर हर घटना के बाद "नई एसओपी" की मांग क्यों उठती है? क्या यह सरकारों की विफलता को छिपाने का तरीका नहीं है? अगर राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन उन गाइडलाइंस का पालन करें, तो इस तरह के हादसे रोके जा सकते हैं। मगर सत्ता और राजनीति का नशा नेताओं को इतना अंधा कर देता है कि उन्हें अपनी लोकप्रियता के लिए जनता की जान की परवाह नहीं रहती।

रोड-शो: प्रदूषण और अव्यवस्था का कारण

रोड-शो, बाइक रैली और विशाल जुलूस राजनीतिक प्रचार का सबसे शोरगुल वाला रूप बन चुके हैं। इन आयोजनों में सैकड़ों-हज़ारों गाड़ियां, डीजे, लाउडस्पीकर और पेट्रोल-डीजल की बर्बादी से हवा में ज़हरीला धुआं भर जाता है। बड़ी मात्रा में बैनर-पोस्टर, प्लास्टिक की बोतलें और कूड़ा सड़कों पर फैलता है, जिससे शहरों का पर्यावरण और स्वच्छता दोनों प्रभावित होते हैं। चुनाव आयोग के मौजूदा नियमों में साफ कहा गया है कि रोड-शो सिर्फ छुट्टी के दिन आयोजित किए जा सकते हैं ताकि आम जनता को यातायात असुविधा न हो। लेकिन हकीकत यह है कि लगभग हर राज्य में यह नियम खुलेआम तोड़ा जा रहा है। स्कूलों, अस्पतालों, ब्लड बैंक और आवश्यक सेवाओं वाले इलाकों में भीड़भाड़ वाले रोड-शो आयोजित हो रहे हैं, जिससे न केवल आम लोगों का जीवन बाधित होता है, बल्कि मरीजों और छात्रों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। वास्तविकता यह है कि रोड-शो अब राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का साधन बन चुके हैं — भीड़ दिखाना ही लोकप्रियता का पैमाना समझा जाता है। इस प्रवृत्ति ने लोकतांत्रिक विमर्श को भीड़ तंत्र में बदल दिया है।

प्रशासनिक लापरवाही और कानूनी ढिलाई

भीड़ प्रबंधन के लिए सरकार के पास पर्याप्त कानून और गाइडलाइंस मौजूद हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम (NDMA), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), पुलिस मैनुअल आदि। लेकिन इन्हें अमल में लाने की इच्छा-शक्ति का अभाव है। उदाहरण के लिए, रोड-शो की अनुमति से पहले प्रशासन को आयोजकों से यह जानकारी लेनी चाहिए कि कितने वाहन, कितने प्रतिभागी और कितने सुरक्षाकर्मी रहेंगे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और जरूरी सेवाओं के लिए वैकल्पिक मार्ग खुले रहें। परंतु अधिकांश जगह यह सब कागजों में सिमटकर रह जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि राजनीतिक दबाव में प्रशासन नियमों को नजरअंदाज कर देता है। पुलिस अधिकारी जानते हैं कि किसी बड़े नेता की रैली में भीड़ नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठाने पर उनका तबादला हो सकता है, इसलिए वे जोखिम नहीं लेते। परिणामस्वरूप सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ जाती हैं और हादसे हो जाते हैं। इन घटनाओं में नेताओं और आयोजकों की आपराधिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर रोड-शो में किसी की मौत होती है तो आयोजक और संबंधित राजनेता पर धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) और धारा 336 (जीवन को खतरे में डालना) के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए।

जनता की मानसिकता और राजनीतिक पाखंड

राजनीतिक रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए मुफ्त खाना, नकद, शराब या कपड़ों का वितरण आम बात है। गरीब और बेरोज़गार तबका इसे उत्सव समझकर शामिल हो जाता है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं होता कि उसकी जान किस खतरे में है। राजनीतिक दल जनता को सिर्फ भीड़ के रूप में देखते हैं — इंसान के रूप में नहीं। वहीं जनता भी नेताओं के वादों और "लोकप्रिय चेहरों" के मोह में फंसकर अपने अधिकारों की अनदेखी करती है। यह मानसिकता बदलनी होगी। दूसरी ओर, जब कोई मशहूर व्यक्ति, अभिनेता या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस अराजकता के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो राजनीतिक ट्रोल उसे "विरोधी दल का एजेंट" कहकर बदनाम करने लगते हैं। आधव अर्जुन की टिप्पणी को भी ऐसे ही राजनीतिक चश्मे से देखा गया, जबकि उनका दर्द मानवीय था, राजनीतिक नहीं। अगर समाज खुद यह तय कर ले कि रोड-शो में न जाएं, भीड़ न बनें, तो नेताओं को मजबूरन यह दिखावे बंद करने होंगे।

चुनाव आयोग की भूमिका और आवश्यक सुधार

भारत का चुनाव आयोग संवैधानिक रूप से स्वतंत्र संस्था है, जिसका दायित्व केवल चुनाव कराना ही नहीं बल्कि उनका शांतिपूर्ण और निष्पक्ष आयोजन सुनिश्चित करना भी है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आयोग की भूमिका पर सवाल उठे हैं कि वह बड़ी पार्टियों के दबाव में निर्णय लेता है या देर से प्रतिक्रिया करता है। अब समय आ गया है कि चुनाव आयोग सख्त और दूरदर्शी रुख अपनाए।

चुनाव न सिर्फ स्वतंत्र हों, बल्कि दिखें भी मुक्त

सौगातों और नैतिकता के बीच फंसा लोकतंत्र

लोकतंत्र की आत्मा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में बसती है। चुनाव केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह उस भरोसे की परीक्षा है जो जनता अपने प्रतिनिधियों और व्यवस्था पर जताती है। यही कारण है कि भारतीय संविधान और चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाए रखने के लिए अनेक प्रावधान किए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब सरकारें चुनाव से ठीक पहले "जनकल्याण" के नाम पर हजारों करोड़ रुपए की सौगातें बांटने लगती हैं, तो क्या यह नैतिक रूप से सही माना जा सकता है? क्या यह मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश नहीं है?

बिहार का ताज़ा उदाहरण: राजनीति और नैतिकता की टकराहट

6 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य आयुक्तों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। यह जानकारी पहले से दे दी गई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4 बजे होगी। लेकिन ठीक एक घंटे पहले यानी दोपहर 3 बजे, बिहार की सत्तारूढ़ एनडीए सरकार ने "मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना" के तहत 21 लाख महिलाओं के खातों में कुल 2100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। हर महिला को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने उसी दिन पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के एक हिस्से का उद्घाटन भी कर दिया। अब सवाल यह है कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से ठीक पहले सरकार द्वारा इतनी बड़ी राशि जनता में बांटना क्या सिर्फ एक संयोग था या एक सुनियोजित राजनीतिक कदम? तकनीकी रूप से यह गैर-कानूनी नहीं कहा जा सकता क्योंकि आचार संहिता उस वक्त तक लागू नहीं हुई थी, लेकिन क्या यह कानून की भावना के विरुद्ध नहीं है? साफ है, यह कदम "नैतिकता" की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। जनता के टैक्स से जमा किए गए धन को "विकास योजना" के नाम पर अंतिम समय में बांट देना किसी भी दृष्टि से लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। इसे खुले तौर पर चुनावी रिश्वत कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी।

रेवड़ियों की राजनीति और प्रधानमंत्री की स्वयं की टिप्पणी

विडंबना यह है कि कुछ समय पहले स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "रेवड़ी संस्कृति" (Freebies Culture) की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की प्रवृत्ति देश की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र दोनों को कमजोर करती है। उनका कहना था कि जनता को भ्रमित करने वाली योजनाएं "लालच की राजनीति" को बढ़ावा देती हैं और जनता के दीर्घकालिक हितों के खिलाफ हैं। लेकिन जब यही रवैया राज्यों में सत्तारूढ़ "डबल इंजन सरकारों" द्वारा अपनाया जाता है, तो यह दोहरे मापदंडों को उजागर करता है। बिहार की घटना इसी विरोधाभास का एक उदाहरण है।

चुनाव की पवित्रता और जनता का भरोसा

चुनाव प्रक्रिया का उद्देश्य सिर्फ मतदान कराना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता बिना किसी दबाव, प्रलोभन या भय के अपने विवेक से वोट डाल सके। लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब उसकी बुनियाद – यानी जनता का विश्वास – अटूट बना रहे। यदि जनता को यह महसूस होने लगे कि सत्ता में बैठे लोग सरकारी धन का दुरुपयोग कर चुनावी लाभ ले सकते हैं, तो उस भरोसे की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव न केवल "स्वतंत्र" हों, बल्कि "दिखें भी स्वतंत्र।" क्योंकि लोकतंत्र की प्रतिष्ठा केवल उसके परिणामों से नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया की शुचिता से तय होती है जिसके ज़रिए परिणाम तक पहुंचा जाता है।

शेषन युग: जब चुनाव आयोग ने अपनी शक्ति दिखाई

आज भारत में जो चुनाव अपेक्षाकृत निष्पक्ष और संगठित ढंग से संपन्न होते हैं, उसकी नींव बहुत हद तक एक व्यक्ति – टी. एन. शेषन – ने रखी थी। 1990 से 1996 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे शेषन ने भारतीय लोकतंत्र में प्रशासनिक नैतिकता का नया अध्याय लिखा। उनसे पहले चुनावों के दौरान बूथ कैप्चरिंग, हिंसा, बैलट बॉक्स से छेड़छाड़, शराब और नकदी का बंटवारा आम बात थी। सरकारी मशीनरी का खुला दुरुपयोग होता था। लेकिन शेषन ने इस संस्कृति को जड़ से हिला दिया। उन्होंने सबसे पहले सरकारी तंत्र के दुरुपयोग और मतदाताओं को प्रभावित करने वाली हर गतिविधि पर सख्ती से रोक लगाई। शराब और धन वितरण पर कार्रवाई हुई। उन्होंने मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) को अनिवार्य बनाने की दिशा में काम किया, चुनावी खर्च पर सीमा तय की और संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती सुनिश्चित की। परिणामस्वरूप बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं में भारी कमी आई और मतदान का वातावरण अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बना।

आदर्श आचार संहिता: कानूनी नहीं, लेकिन नैतिक ढाल

टी. एन. शेषन ने जिस चीज़ को सबसे मज़बूत बनाया, वह थी "आदर्श आचार संहिता" (Model Code of Conduct)। यह आयोग द्वारा जारी एक ऐसा दस्तावेज़ है जो कानून की तरह बाध्यकारी तो नहीं, लेकिन नैतिक और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद प्रभावशाली है। आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल किसी भी प्रकार से सरकारी संसाधनों, योजनाओं या अधिकारों का उपयोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए न करे। यह संहिता चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से लेकर परिणाम घोषित होने तक लागू रहती है। इसके अंतर्गत सत्तारूढ़ दल या मंत्री मतदाताओं को प्रभावित करने वाली किसी भी नई योजना, परियोजना, उद्घाटन या धन-वितरण की घोषणा नहीं कर सकते। यही कारण है कि कई बार आचार संहिता लागू होते ही उद्घाटन कार्यक्रम, सरकारी विज्ञापन और लाभ योजनाएं रोक दी जाती हैं।

नैतिक बनाम कानूनी दृष्टिकोण

अक्सर नेता यह तर्क देते हैं कि चुनाव से पहले की योजनाएं "नियमों के अनुसार" हैं क्योंकि आचार संहिता अभी लागू नहीं हुई होती।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर नेमी चंद कायथ 'बेस्ट प्रोग्राम ऑफिसर' से सम्मानित

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में नेमी चंद कायथ को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए 'बेस्ट प्रोग्राम ऑफिसर' के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया। यह कार्यक्रम राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सम्मानित करना था। समारोह को संबोधित करते हुए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य भी अत्यंत आवश्यक है और राज्य सरकार प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लोगों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेषज्ञों की मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। नेमी चंद कायथ को यह पुरस्कार मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके सराहनीय प्रयासों और समर्पण के लिए दिया गया। इस अवसर पर विभिन्न जिलों और महाविद्यालयों के अन्य प्रतिनिधियों को भी उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुधांश पंत और विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

भारत को तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बनाएं- भजनलाल शर्मा

-मुख्यमंत्री ने 21 मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल पहनाकर दी डिग्रियां

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जो राष्ट्र नई तकनीक और नवाचारों में अग्रणी बनते हैं, वही दुनिया में नेतृत्व करते हैं। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने नवाचार, उद्यमिता और वैश्विक स्तर के अनुसंधान के माध्यम से राजस्थान का नाम ऊंचा किया है। एमएनआईटी अब ज्ञान, नवाचार और राष्ट्रसेवा का प्रतीक बन चुका है। यह युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे इस विरासत को आगे बढ़ाएं और भारत को केवल तकनीक का उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि निर्माता भी बनाएं।

शर्मा शनिवार को मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें अपनी कर्मशीलता को प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप्स, उद्योगों और कक्षाओं तक लेकर जाना है। भविष्य सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटर, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है। वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद, रणनीतिकार और नवप्रवर्तक भविष्य के नायक होंगे। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी वह कुंजी है जो समृद्धि, सुरक्षा और सम्मान के द्वार खोलती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएनआईटी का एन.आई.आर.एफ. की रैंकिंग में उत्तर भारत के शीर्ष एन.आई.टी. के रूप में स्थान प्राप्त करना हम सभी के लिए गौरव की बात है। इस संस्थान की अनुसंधान यात्रा में 249 परामर्श परियोजनाएं, 13 करोड़ से अधिक की राशि के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिम कमान, रैडॉक्स इंजीनियरिंग और परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के साथ एम.ओ.यू. इस संस्थान के लिए नए आयाम स्थापित करेगा।

एमएनआईटी ने डिग्रियों को डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना किया प्रारंभ

शर्मा ने कहा कि एमएनआईटी से इस वर्ष 150 से अधिक विद्यार्थी डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त कर रहे हैं तथा 30 से अधिक दिव्यांग विद्यार्थी स्नातक हुए हैं। इस वर्ष 77 अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों का भी संस्थान में प्रवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के सभी एन.आई.टी. में सबसे अधिक छात्रा-छात्र अनुपात प्राप्त कर यह संस्थान नारी सशक्तीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। नई शिक्षा नीति को यहां के पाठ्यक्रम में लागू कर विद्यार्थियों को नीति के अनुरूप प्रशिक्षण मिल रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थान ने प्रौद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए डिग्रियों को राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी के डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड करना प्रारंभ किया है।

भारत अगले दो दशकों में दुनिया की शीर्ष आर्थिक ताकतों में होगा शामिल—

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उपलब्धि अर्जित कर चुका है और अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। अगले दो दशकों में भारत दुनिया की शीर्ष आर्थिक ताकतों में शुमार होगा। उन्होंने कहा कि हमारे युवा, हमारा कौशल और हमारी तकनीकी क्षमता अभूतपूर्व होगी और इस परिवर्तन के केंद्र में युवा शक्ति और एम.एन.आई.टी. जैसे संस्थान होंगे।

युवाओं को स्टार्टअप पॉलिसी ने नवाचार और उद्यमिता के नए अवसर किए प्रदान—

शर्मा ने कहा कि सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी ने राज्य के युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के नए अवसर प्रदान किए हैं। एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी लागू की गई है। स्कूली छात्रों में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आई-स्टार्ट कार्यक्रम का विस्तार किया है। इसके तहत 66 आईस्टार्ट लॉन्चपैड नेस्ट स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024-25 में 2 हजार 28 स्टार्टअप्स पंजीकृत हुए तथा 300 स्टार्टअप्स को आई-स्टार्ट फंड से लगभग 11 करोड़ रुपये की फंडिग प्रदान की गई। लर्न, अर्न एण्ड प्रोग्रेस प्रोग्राम (लीप) कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

युवाओं के लिए अर्ली कैरियर प्रोग्राम (टेकबी) किया शुरू—

मुख्यमंत्री ने कहा कि बारहवीं कक्षा के तुरंत बाद राज्य के युवाओं के लिए कौशल उन्नयन और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से अर्ली कैरियर प्रोग्राम (टेकबी) शुरू किया है। रिप्स 2024 के तहत, आईटी, आईटीईएस प्रोजेक्ट्स को एसेट-क्रिएशन इंसेंटिव के लिए 3 विकल्प दिए जा रहे है, जिनमें 7 वर्षों तक 75 प्रतिशत एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति, 20 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी व 1.4 प्रतिशत टर्नओवर-लिंक्ड इंसेंटिव शामिल हैं। इनमें से किसी एक का लाभ लिया जा सकता है।

नए आपराधिक कानूनों का एक साल

-जयपुर PHQ में प्रदर्शनी आयोजित, 'दंड के बजाय न्याय' पर फोकस

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। देश में लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन का एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होने के अवसर पर शनिवार को जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय (PHQ) में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य नए कानूनों से आए सकारात्मक बदलावों और उनकी मूल भावना को आमजन और पुलिसकर्मियों तक पहुंचाना था।

बदले गए 160 साल पुराने कानून-

गौरतलब है कि 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) देशभर में लागू हुए थे। इन कानूनों ने 160 साल से भी अधिक पुराने औपनिवेशिक युग के कानूनों—आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम—की जगह ली है।

न्याय-केंद्रित व्यवस्था पर जोर-

प्रदर्शनी में विभिन्न चार्ट्स और डिस्प्ले के माध्यम से यह दर्शाया गया कि नए कानूनों की आत्मा 'दंड' के बजाय 'न्याय' प्रदान करने पर केंद्रित है। इसमें टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक विज्ञान के अनिवार्य उपयोग पर प्रकाश डाला गया, जिससे जांच प्रक्रिया को पारदर्शी, वैज्ञानिक और सुगम बनाया गया है। साथ ही, प्रदर्शनी में नागरिक और पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण, समयबद्ध न्याय प्रणाली, और अपराधियों के प्रति अपनाए गए नए दृष्टिकोण (गंभीर अपराधियों के लिए सख्ती और सामान्य अपराधों के लिए सुधार का प्रावधान) जैसी विशेषताओं को भी प्रमुखता से दिखाया गया। यह आयोजन इस ऐतिहासिक कानूनी सुधार की पहली वर्षगांठ का प्रतीक रहा।

भारतीय अंग प्रत्यारोपण सोसाइटी वार्षिक समारोह

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने विद्यालय स्तर से ही अंगदान के लिए जागरूकता से जुड़ी शिक्षा का प्रसार करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि अंगदान महादान है। हमारे यहां लाखों लोग अंग प्रत्यारोपण नहीं होने से अपनी जान गंवा देते हैं। इन मौतों को रोकने के लिए अंगदान से जन जन को जोड़ा जाए। राज्यपाल बागडे शनिवार को भारतीय अंग प्रत्यारोपण सोसाइटी द्वारा आयोजित समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंगदान महादान है। यह किसी के जीवन को बचाने जैसा है। उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालयों में अंगदान की शिक्षा सम्मिलित किए जाने का भी सुझाव दिया। बागडे ने कहा कि अंग दान को जन आंदोलन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि भारत में प्राचीन काल से हो अंगदान की परम्परा रही है। उन्होंने महर्षि दधीचि का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने असुरों के वध के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। उनकी हड्डियों से इंद्र के लिए वज्र नाम का अस्त्र बनाया गया था। राज्यपाल ने चिकित्सकों को अंगदान के लिए प्रेरित करने के साथ आम जन को रोगों से बचाव, खान पान और जीवन शैली में सुधार करने हेतु भी कार्य किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने भारत में अंगदान करने वाले लोगों का उदाहरण देते हुए उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। आरंभ में राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया।

जयपुर में खाद्य सुरक्षा टीम ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम

- 1 हजार 275 किलो मिलावटी मसालों का जखीरा किया बरामद

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। राज्य सरकार के "शुद्ध आहार – मिलावट पर वार" अभियान के तहत जयपुर में खाद्य सुरक्षा दल ने आज एक बड़ी सफलता हासिल की। टीम ने मिलावटी हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर की लगभग 1275 किलोग्राम मात्रा जब्त कर एक संगठित मिलावट नेटवर्क का पर्दाफाश किया।

यह कार्रवाई आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के मार्गदर्शन में की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मुरलीपुरा क्षेत्र में एक लोडिंग ऑटो को पकड़ा, जिसमें मसालों से भरे 11 कट्टे पाए गए। पूछताछ के आधार पर टीम कर्ती इंटरप्राइजेज नामक फर्म तक पहुंची, जहां निरीक्षण के दौरान कुल 29 कट्टों में लगभग 1275 किलो मिलावटी मसाले बरामद किए गए।

जांच में पाया गया कि इस व्यापारी के यहां से पूर्व में लिए गए नमूने भी "अनसेफ" घोषित किए जा चुके हैं। अब खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि मिलावटखोरी के विरुद्ध जिला प्रशासन की ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। नियमित समीक्षा बैठकों में ऐसे व्यापारियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा, वीरेंद्र कुमार सिंह, नरेश कुमार चेजारा, विशाल मित्तल, नरेंद्र शर्मा एवं पवन कुमार गुप्ता सक्रिय रूप से शामिल रहे।

थाना मालपुरा गेट सांगानेर पुलिस की साहसिक कार्यवाही दो शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार

सादिक हिन्दस्तानी

सांगानेर (रॉयल पत्रिका)। पुलिस थाना मालपुरा गेट सांगानेर पूर्व के जांबाज पुलिस द्वारा तुरंत कार्यवाही कर महिला से बैग छीन कर भागने वाले दो शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व संजीव नैन आईपीएस ने बताया कि जयपुर शहर में लूट, चोरी, नकबजनी की वारदात करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समस्त सहायक पुलिस आयुक्त एवं थानाधिकारियों को अधिक से अधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। एक महिला परिवादिया सरोज जैन पत्नी उत्तम कुमार जैन निवासी एस डी सी यूरो एक्जोटिक फ्लैट नंबर 517 कुशलनगर न्यू सांगानेर रोड रिको पुलिया के द्वारा 10 अक्टूबर 2025 को मैं चोमू बाग स्थित पार्श्वनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी। इस दौरान पीछे से एक मोटरसाइकिल बुलेट पर सवार दो लड़के मेरा बैग छीन कर ले गए। जिसमें दो चांदी के कलश ,दो चांदी की थाली, एक चांदी की प्लेट, एक चांदी का टोना, एक चांदी का मग, एक चांदी की माला और 520 रुपए नगद रखे थे। बैग को लेकर भाग गए। वारदात की गंभीरता को देखते हुए सहायक पुलिस आयुक्त विनोद कुमार शर्मा के सुपरविजन में एवं पुलिस थाना मालपुरा गेट इंचार्ज उदयभान यादव के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा पूर्व में चालान सुधा अपराधियों से पूंछताछ की गई। सी सी टीवी फुटेज खंगालें गए। हुलिया एवं प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को चिन्हित किया गया। बाल किशन उर्फ बल्लू पुत्र ज्ञानचंद जाति कुम्हार उम्र 26 निवासी बागड़ा हॉस्पिटल के पास मद रामपुरा तथा लक्ष्मण उर्फ लछी पुत्र काना उर्फ कन्हैया उम्र 30 साल जाति माली निवासी पंचकुइया टोंक। को गिरफ्तार कर छीने गए माल को बरामद किया गया। यह दोनों शातिर अपराधी हैं। इनके ऊपर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस थाना मालपुरा गेट सांगानेर की गठित टीम में बृजमोहन, उदयभान, करण सिंह, युवराज, पुष्पेंद्र, पवन कुमार आदि शामिल रहे। उक्त कार्यवाही में कानि. कर्ण सिंह 10894 तथा कानि. योगराज 9705 की विशेष भूमिका रही।

मद्रासी बाबा रहमतुल्ला अलेह का 3 दिवसीय वार्षिक उर्स सम्पन्न

मनोहरपुर (रॉयल पत्रिका)। जयपुर के शास्त्री नगर पुलिस थाने के पास वाले मुस्लिम कब्रस्तान में स्थित हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिक हजरत मद्रासी बाबा रहमतुल्ला अलेह का 3 दिवसीय वार्षिक उर्स कूल की रस्म के साथ में विधिवत सम्पन्न हो गया। मुतवली व सज्जादा नशीन खलीफा मोहम्मद सलीम ने बताया कि 09 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 9 बजे कुरानख्वानी हुई रात्रि 9 बजे बाद में मिलादुन्नबी कमेटी द्वारा मिलाद शरीफ की गई जिसमें खुदा के हुकम व मोहम्मद साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने की बात कही गई। ईसी प्रकार 10 अक्टूबर शुक्रवार की शाम को चादर पेश की गई रात्रि 9 बजे बाद में राजस्थानी प्रसिद्ध कव्वाल पार्टी द्वारा बाबा की मान मनुहार की गई। शनिवार 11 अक्टूबर को सुबह 9 बजे रंग व कूल 10 बजे फातेहा, लंगर व दुआ हुई। इसी के साथ मे उर्स का समापन हुआ। सराहनीय कार्य करने वालो पत्रकारों व सूफ़ियों की दस्तारबंदी की गई।

विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए जिला प्रशासन का नवाचार

- 5 सरकारी विद्यालयों में खगोल विज्ञान प्रयोगशालाएं की गई स्थापित

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को साकार करने और विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि एवं प्रयोगात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में जयपुर जिले में खगोल विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। शनिवार को गोविंदगढ़ ब्लॉक के दो विद्यालयों — पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन, चौमू और महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, भोजलावा में खगोल विज्ञान प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया गया। इन प्रयोगशालाओं का निर्माण फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत किया गया है। जिला प्रमुख रमा देवी चोपड़ा एवं जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती प्रतिभा वर्मा की मौजूदगी में आयोजित हुए कार्यक्रम में ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए जिला प्रमुख श्रीमती रमा देवी चौपड़ा ने कहा कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नई संभावनाओं से जोड़ने का माध्यम बनेगी। प्रयोगशाला आधारित शिक्षा विद्यार्थियों के करियर विकास में सहायक सिद्ध होगी। वहीं, श्रीमती प्रतिभा वर्मा ने बताया कि खगोल विज्ञान प्रयोगशालाएं विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का नया आकाश खोलेंगी। यह सक्षम जयपुर के विज़न के अनुरूप शिक्षा को बहुआयामी बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिला जिला परिषद जयपुर के सहयोग से नवाचार के रूप में 5 सरकारी विद्यालयों में खगोल विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

इन प्रयोगशालाओं का उद्देश्य विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान की गहराइयों से परिचित कराना और खगोलीय घटनाओं को प्रयोगात्मक रूप से समझने का अवसर देना है। उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला में 69 आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, जिनमें चंद्रमा की कलाएं, सौर ऊर्जा किट, सौर फ़िल्टर, परमाणु गेंदें, डोबसोनियन दूरबीन, किरण ऑप्टिक किट, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण मॉडल, गुरुत्वाकर्षण-विरोधी प्रयोग, उत्तल दर्पण, हृदय व मस्तिष्क मॉडल, रसायन एवं जीव विज्ञान किट शामिल हैं। इन प्रयोगशालाओं का निर्माण कार्य फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर के सहयोग से एस्ट्रोस्कोप कंपनी द्वारा किया गया है। कंपनी की ओर से विज्ञान शिक्षकों और विद्यार्थियों को उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक दीपक शुक्ला, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कृपानिधि त्रिपाठी, कैपिटल फाइनेंस से सीताराम (प्रबंधक), विद्यालय स्टाफ तथा स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार प्राथमिकता

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने शनिवार को उदयपुर के स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राजस्थान के पहले केएमसी लाउंज का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन देते हुए खराडी ने कहा कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वाच्च प्राथमिकता है तथा इस हेतु राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। राजस्थान के इस पहले कंगारू मदर केयर लाउंज का उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता एवं जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिया डाबी के निर्देशन में निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया है। मंत्री खराड़ी ने कहा कि खेरवाड़ा जो एक आकांक्षी ब्लॉक है, इस तरह की पहल ग्रामीण अंचल में माता और नवजात शिशुओं को एकीकृत एवं सम्मानजनक देखभाल उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। मंत्री खराड़ी ने कहा कि केएमसी लाउंज मॉडल के तहत नवजात एवं मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम को और मजबूती मिलेगी इसके साथ ही एएनसी अवधि में उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान कर उन्हें सही देखभाल प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार यह पहल आकांक्षी ब्लॉक के मानकों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए अहम योगदान देगी। इससे पूर्व मंत्री खराड़ी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित आधुनिक लैब यूनिट का भी शुभारंभ किया।

ग्रामीण सेवा शिविर का किया निरीक्षण-

मंत्री खराड़ी ने उदयपुर के पलसिया ग्राम पंचायत में लगे ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया तथा विभिन्न विभागों के काउंटर पर जाकर अधिकारी एवं कर्मचारियों से आमजन के लिए किया जा रहे कार्य व योजनाओं की जानकारी ली तथा कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचे और हर पात्र व्यक्ति को उसका हक मिले यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने शिविर में अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों पर रोष व्यक्त करते हुए उपखंड अधिकारी से उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया।

JSK हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ

मनोहरपुर (रॉयल पत्रिका)। क्षेत्रवासियों के लिए राहत की बड़ी खबर है कि अब हड्डियों से जुड़ी किसी भी समस्या के इलाज के लिए जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनोहरपुर शहर के मंगलम कॉलोनी सर्किल के पास JSK हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ किया गया है। इस हॉस्पिटल में वरिष्ठ आर्थोपेडिक, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉ. राधेश्याम यादव अपनी 24 घंटे उपलब्धता के साथ सेवाएँ देंगे। अब फ्रैक्चर, जोड़ प्रत्यारोपण, स्पोर्ट्स इंजरी, हड्डियों के दर्द और रीढ़ की हड्डी से संबंधित सभी बीमारियों का आधुनिक उपचार मनोहरपुर में ही संभव होगा।

स्थानीय लोगों ने कहा कि डॉ. यादव जैसे अनुभवी विशेषज्ञ का मनोहरपुर में उपलब्ध होना पूरे क्षेत्र के लिए एक आशीर्वाद और सराहनीय पहल है। इससे ग्रामीण इलाकों के मरीजों को समय, धन और यात्रा की परेशानी से मुक्ति मिलेगी।

आवश्यक नम्बर

रॉयल पत्रिका

बिजली फॉल्ट के लिए		**पानी के लिए**	
टोल फ्री नंबर	18001806507	जलदाय कार्यालय	2706624
वॉट्सएप नंबर	9414037085	फायर ब्रिगेड	2747400
कस्टमर केयर	2203000	**मेडिकल इमरजेंसी के लिए**	
आईवीआरएस	1912	एंबुलेंस	102/108
कचरा गाड़ी के लिए		एसएमएस इमरजेंसी	2518333
ग्रेटर	2747400	महिला चिकित्सालय	22610616
सीवरेज लीकेज	2607500	जनाना हॉस्पिटल	22378721
हेरिटेज	2607500	SDMH	22574189
टोल फ्री नंबर	14420	SMS ब्लड बैंक	22518222
पुलिस की मदद के लिए		कल्याण ब्लड बैंक	22721771
साइबर क्राइम	1930/2360094	**घायल पशुओं के लिए**	
कंट्रोल रूम	2388435/36/37/38	नगर निगम	2747400
ट्रैफिक कंट्रोल रूम	2565630	बर्ड बाइक	9887345580
चाइल्ड हेल्पलाइन	1098	हेल्प इन सफरिंग	8107299711
महिला हेल्पलाइन	1090	जनमंच ट्रस्ट	7230055800
मुख्यमंत्री पोर्टल	181	पशु चिकित्सालय	2747400

दुधवाखारा में जन सेवा विकास समिति की बैठक संपन्न

मोहम्मद अली पठान

चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव में जनसेवा विकास समिति दुधवाखारा की एक बैठक का आयोजन तालाब पायतन पर डॉ. रामावतार शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में सरपंच प्रतिनिधि देवकरण कस्वां के अलावा बड़ी संख्या में समिति के सदस्यों व गांव के गणमान्य नागरिकों नें भाग लिया। बैठक में जोहड़ पायतन पर स्थित भवन की मरम्मत, जोहड़ के रखरखाव और मरम्मत तथा पशुओं के लिए खेल और नियमित जल आपूर्ति पर विचार किया गया। बैठक में डॉ. रामावतार शर्मा ने आश्वासन दिया कि सभी मरम्मत कार्यों के लिए वित्तीय सहायता के लिए वह प्रबंध करा देंगे।इसके साथ ही सदस्यों द्वारा सुझाए दिए गए अन्य विषयों पर तथा हायर सेकेण्डरी स्कूल में निर्मित ग्रामीण लाइब्रेरी शुरू करने, गांव से हाइवे तक सड़क की मरम्मत व उसकी चोड़ाई बढ़ाना, पशुओं के लिए अतिरिक्त एवं खेलों के लिए निर्माण आदि पर भी विचार किया गया।बैठक में डॉ. रामावतार शर्मा ने कहा कि गांव में चल रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम को और सघन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गांव में हर घर में फलदार वृक्ष लगाएं तथा जोहड़ पायतन में निंबू, आंवला, जामुन, सहजन और छायादार वृक्ष लगाएंगे। बैठक में शामिल सभी ग्रामवासियों ने अपने सुझाव दिए। अंत में डॉ. रामावतार शर्मा और सरपंच प्रतिनिधि देवकरण कस्वां नें बटन दबाकर पानी वितरण के लिए लगवाई गई मोटर का शुभारंभ किया। समिति के अध्यक्ष ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया।

प्लास्टिक मुक्त भारत की थीम पर राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर आयोजित

सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)। निकटवर्ती शेरपुर खिलचीपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय सेवा योजना का द्वितीय एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना +2 की कार्यक्रम अधिकारी ममता मीना के निर्देशन में किया गया। सर्वप्रथम शिविर का उद्घाटन मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य हनुमान प्रसाद मीणा द्वारा किया गया। द्वितीय एकदिवसीय शिविर की थीम- प्लास्टिक मुक्त भारत के आधार पर थी। शिविर में सभी स्वयंसेवको द्वारा भाग लिया गया। कार्यक्रम अधिकारी ममता मीना ने सभी स्वयंसेवक और सेविकाओं को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने हेतु प्रेरित किया। प्लास्टिक की थैली के स्थान पर कपड़े के बेग का प्रयोग करने हेतु श्रीमती दुर्गा मीणा यथावत प्रधानाचार्य द्वारा स्वयंसेवकों को समझाया। व्याख्याता चिरंजी लाल सैनी, रघुवर दयाल मथुरिया द्वारा सभी स्वयंसेवक सेविकाओं को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की सलाह दी। गिर्राज प्रसाद स्वर्णकार अध्यापक ने भी सभी छात्र-छात्राओं को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया।प्रधानाचार्य हनुमान प्रसाद मीणा प्रसाद मीणा द्वारा भी सभी स्वयंसेवक को अपने घर गांव आदि में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने हेतु प्रेरित किया। इसके बाद सभी स्वयंसेवकों ने विद्यालय परिसर में पड़े हुए प्लास्टिक वेपर्स आदि को इकट्ठा किया और जलाया। संपूर्ण विद्यालय परिसर की सफाई की। सभी स्वयंसेवकों को अल्पाहार भी दिया गया।इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य संजय कुमार जैन, वरिष्ठ अध्यापिका दीपिका, अध्यापिका अनीता चंदेल, भोला शंकर जेलिया, कन्हैयालाल आदि स्टाफ उपस्थित रहा।

टांकरड़ा के डॉ. मधुर हरसोलिया ने जीता बेस्ट रेजीडेंट का खिताब

चौमूं (रॉयल पत्रिका)। राजस्थान आप्थल्मॉलोजिक सोसायटी की ओर से पुष्कर में आयोजित 47वीं वार्षिक कांफ्रेंस में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के रेजीडेंट व ग्राम टांकरड़ा के डॉ. मधुर हरसोलिया पुत्र डॉ. (मेजर) आर.एस. हरसोलिया ने बेस्ट रेजीडेंट ऑफ द ईयर का खिताब जीतकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। 3 से 5 अक्टूबर तक आयोजित तीन दिवसीय कांफ्रेंस में देश भर के 500 नेत्र रोग विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसमें राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध एवं जाने-माने नेत्र विशेषज्ञों ने अपने-अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। चिकित्सालय के नेत्र विशेषज्ञ डॉ. राजेश सैनी ने रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी एवं डॉ. (मेजर) आर.एस. हरसोलिया ने रेट्रोपुपिलरी इरिस क्ला लेंस इंप्लांटेशन इन अफेकिया पर शोध-पत्र का वाचन किया। इस दौरान डॉ. एल.के. नेपालिया, डॉ. राकेश पोरवाल, डॉ. नीरज खुंगर, डॉ. अरुण क्षेत्रपाल, डॉ. प्रीति लाल, डॉ. विभूति गक्खड, डॉ. सोनेल असेरी सहित कई चिकित्सक मौजूद थे।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर बारी फाउंडेशन ने किए जागरूकता के कार्यक्रम

चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय पर आज बारी फाउंडेशन ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा देना और लोगों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षणों में- मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर चर्चा हुई।
- तनाव प्रबंधन और जागरूकता बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा
- बारी फाउंडेशन के प्रयासों को उजागर करना
- मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना
इस मौके पर B.A.R.I. फाउंडेशन की तरफ़ से हसन खान, रिंकू शर्मा और मोहित ने आम युवाओं को इस बारे में चुरू शहर में अनेक जगह पर युवाओं ओर महिलाओं को इस बारे जागृत रहने की जानकारी दी। इस मौके पर यूसुफ खान नारू, उम्मेद खान, अयूब खान, ज़ाकिर खान केके, सिकन्दर खान एवं शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे ।

सवाई माधोपुर के डॉ. गणपत लाल वर्मा को "क्लिनिकल एक्सीलेंस अवॉर्ड" से सम्मानित किया गया

सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)। जयपुर स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट (UEM) में आज आयोजित 3rd International Conference on Advancements in Physiotherapy (ICAP 3.0) मेंसवाई माधोपुर के प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. गणपत लाल वर्मा को"Clinical Excellence Award" से सम्मानित किया गया।इस वर्ष सम्मेलन की थीम रही "Bridging the Gap: Physiotherapy Solutions for an Aging Population" ("फिजियोथेरेपी द्वारा वृद्ध होती जनसंख्या के लिए समाधान की दिशा में सेतु निर्माण")। यह सम्मान डॉ. वर्मा को फिजियोथेरेपी क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान, नैदानिक अभ्यास (Clinical Practice) में विशेषज्ञता, निष्ठा और रोगियों की देखभाल में अद्वितीय सेवाओं के लिए प्रदान किया गया। डॉ. गणपत लाल वर्मा सवाई माधोपुर में पिछले कई वर्षों से राधास्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर के माध्यम से लोगों को उपचार एवं पुनर्वास सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने अब तक हजारों मरीजों को स्वस्थ जीवन की राह पर लौटने में सहायता की है। यह उपलब्धि न केवल सवाई माधोपुर के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूरे राजस्थान के फिजियोथेरेपी समुदाय के लिए भी प्रेरणा है।

शिक्षाविद् हाजी रसूल खां अखाण ने दुनिया-ए-फ़ानी को कहा अलविदा

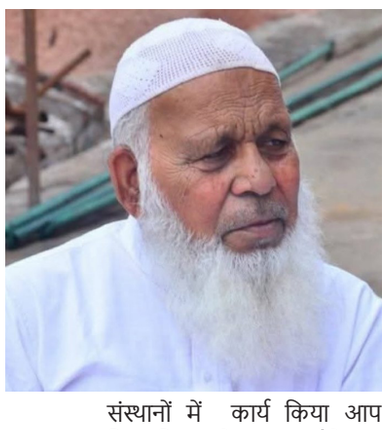

चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय पर शिक्षाविद् हाजी रसूल खां अखाण इस दुनिया-ए-फ़ानी को अलविदा कह गए। आपका आज सुबह इंतकाल हो गया आपका जनाजा दिन में निवास स्थान आथुना मोहल्ला से पंखा सर्किल नई कब्रिस्तान ले जाया गया। जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने जनाजे में शिरकत की जनाजे में सर्व समाज के लोग काफी संख्या में रहे। आपका समाज के अलावा सभी समाजों में अच्छा तालमेल रहा और समाज सेवा की आप एक बेहतरीन शख्शियत के धनी थे। आपने समाज एवं अनेक संस्थानों में कार्य किया आप शिक्षा विभाग से प्रधानाचार्य के पद से रिटायर हुए। और समाज सेवा की। आपके निधन की खबर से शहर व समाज में एक शोक की लहर दौड़ गई। काफी संख्या में राजनेताओं व कर्मचारियों ने शोक व्यक्त किया।

मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना के खिलाफ वकीलों के संगठन ने दिया ज्ञापन

कोटा (रॉयल पत्रिका)। देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना के विरोध में ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसियेशन ऑफ जस्टिस ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
संगठन के कन्वीनर एडवोकेट- अन्सार इंदौरी ने बताया कि राष्ट्रपति के नाम दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि गहरी चिंता है कि कुछ ताकतें " राष्ट्रवाद "के नाम पर देश की संस्थाओं को कमजोर करने और समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं। एडवोकेट दिनेश राय द्विवेदी ने कहा कि हम देश के नागरिकों से अपील करते हैं कि ऐसे बांटने वाले और अपमानजनक कामों को ठुकरायें। संगठन मांग करता हैं कि इस घटना की जांच कराई जाए और जूता फेकने वाले अधिवक्ता पर तत्काल कडी कानूनी कार्रवाई की जाए। केन्द्र सरकार मुख्य न्यायाधीश माननीय बी आर गवई को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करे, असहिष्णुता फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों से सख्ती से निपटा जाय तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति के अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त कदम उठाए। ज्ञापन देने वालों में एडवोकेट मोहम्मद साबिर, एडवोकेट बिलाल नूरी, एडवोकेट अबरार अहमद सहित कई प्रगतिशील अधिवक्ता शामिल थे।

डाक विभागीय अधिकारी एवं कर्मियों ने लिया मतदान का संकल्प

-राष्ट्रीय डाक दिवस विशेष

बारां (रॉयल पत्रिका)। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर एवं सीईओ व नोडल अधिकारी स्वीप राजवीर सिंह चौधरी के निर्देशानुसार 11 नवंबर को अंता विधानसभा उपचुनाव में शत प्रतिशत मतदान के उद्देश्य से राष्ट्रीय डाक दिवस के अवसर पर शुक्रवार को अंता विधानसभा क्षेत्र में स्थित सभी उप डाकघर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, अंता मुख्यालय स्थित उप डाकघर में सह प्रभारी स्वीप अमित भार्गव ने उपस्थित जन को निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर अनिवार्य रूप से मतदान करने का संकल्प कराया, वही उप डाकपाल अवंतिका मीणा ने सभी से मतदान दिवस 11 नवंबर को अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील की, वहीं प्रभारी भार्गव ने निर्वाचन विभाग द्वारा जारी ऑनलाइन ऐप के बारे में विस्तृत जानकारी सहित मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवाये तथा अपने निर्वाचन संबंधी कार्य ऐप के माध्यम से करने के साथ अपने परिचित जन का भी इसके माध्यम से सहयोग करने की बात कही। वहीं उप डाकघर मांगरोल, सीसवाली, अंता के एनटीपीसी स्थित उप डाकघर में भी आयोजन हुआ, इस दौरान डाक सहायक नितेश शर्मा, शाखा पोस्टमास्टर पलायथा, खजूरना कलॉ, राजगढ़, विभागीय अधिकारी, कार्मिक एवं नागरिक मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री शर्मा के ओएएसडी गोविंद पारीक ने सहायक निदेशक सिंगारिया व मीडिया कर्मियों से चर्चा कर लिया फीडबैक

मोहम्मद यासीन

पाली (रॉयल पत्रिका)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ओएएसडी गोविंद पारीक आज शुक्रवार को जिले के अल्प प्रवास पर रहे और उन्होंने सहायक निर्देशक सौरभ सिंगारिया व मीडिया कर्मियों से जिले के बारे में जानकारी ली। पेंशनर भवन में शुजरवार को मीडिया कर्मियों के साथ चर्चा कर फीडबैक लिया व उनके सुझावों के बारे में जाना। सिंगारिया ने विभाग व जिले के वारे में जानकारी दी साथ ही साथ ही जिले के विभिन्न मीडियाकर्मियों ने अनेक सुझाव दिए। साथ ही पारीक ने मीडिया गैलरी का भी अवलोकन किया व मीडिया कर्मियों की सहारा ना की इस अवसर पर इनके मार्गदर्शन के लिए सिंगरिया नें आभार व्यक्त किया व शेखर राठोर, सुभाष त्रिवेदी, श्याम चौधरी, रविंद्र सोनी, मनोज शर्मा, सिकंदर खान, दिनेश चौहान, पन्नालाल चौहान, मुकेश राजा, पवन पांडे, राजीव दवे, सुरेश हेमनानी, नरपत सिंह, युगल किशोर, अनिल ओझा, हेमंत कुमावत, दीपक, आदि अन्य मौजूद रहे।

अध्यक्ष पद के दावेदारों की धड़कने बढ़ी

-आखरी पंक्ति में बैठे कार्यकर्ताओं का मन टटोल रहे हैं कांग्रेस पर्यवेक्षक

शादाब अली

सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)। कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार संगठन सृजन अभियान के तहत सवाई माधोपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का फीडबैक लेने पहुंचे पर्यवेक्षकों ने प्रथम दिन 9 अक्टूबर को सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित किया। जिसमें उन्होंने बताया की कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर आमजन व कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की जाएगी। राहुल गांधी व कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर कांग्रेस में अंतिम पंक्ति के लोगों को तर्जी दी जाएगी।कार्यकर्ता साथी संगठन को मजबूत करें 2028 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लानी हे। लॉ एन ऑर्डर पूरी तरह ठप पड़ा हे,SMS ट्रॉमा अग्निकांड, झालावाड़ स्कूल की छत सरकार पूरी तरह से विफल चल रही हे। पर्यवेक्षकों ने बताया कि हम 8दिन जिला मुख्यालय से लेकर प्रत्येक विधानसभा के ब्लॉक स्तर तक कार्यकर्ताओं से मीटिंग लेंगे व जो भी नाम सुझाव में आएंगे उनको पैनल बनाकर भेज दिए जाएंगे। ऐसे में दावेदारों की धड़कने बढ़ने लगी हे लगातार पर्यवेक्षकों के दौरे बैठके जारी हे।कांग्रेस में सभी दावेदार अपने-अपने कयास लगाकर स्वयं को जिला अध्यक्ष मनवाने में लगा हुआ हे।परन्तु कांग्रेस यदि सही सुझाव व बिना शिफारिश के अध्यक्ष को चुनेगी तो संगठन में मजबूती आएगी ओर पार्टी को बहुत फायदा होगा।

जिले में चल रहे सहकार सदस्यता अभियान के तहत जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने ली बैठक

चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय पर जिले में सहकारिता विभाग की चल रही सहकारी संस्थाओ में सदस्यता अभियान कार्यक्रम के तहत शनिवार को जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय चूरू में बैठक हुई जिसमें सहकारी संस्थाओं में सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई। जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि प्रदेश के निर्देशानुसार जिले में 02 अक्टुबर से 25 अक्टुबर तक चल रही सहकारी विभाग की सहकारी संस्थाओं में सदस्यता अभियान के तहत जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है जिसमें लोगो को सहकार की उपयोगिता बताकर उन्हे इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता अभियान पूर्णमनोयोग से चल रहा है। केन्द्रिय सहकारिता मंत्री अमित शाह इस मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे है और गांव से लेकर शहर एवम् कस्बे से लेकर ढाणी तक सहकारिता अभियान को मजबूती देने के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होने आज की व्यवस्था में सहकार अभियान को महत्वपूर्ण बताते हुऐ कहा कि इस योजना से समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने अल्प अंशदान से बड़ा कार्य खड़ा करने में सक्षम है इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे है। उन्होने कहा कि सहकारिता अभियान से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। इस अभियान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्वदेशी अपनाओं अपील का भी काफी प्रभाव पड़ा है। इस अवसर सहकारिता आंदोलन सदस्यता अभियान के जिला संयोजक फतेहचन्द सोती ने कहा कि सहकारिता का अभियान जहां देश को अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मजबूती प्रदान करता है वही इससे जुड़े हुऐ सदस्यो को भी आर्थिक संबल मिलता है और उनके मन में राष्ट्र के विकास में योगदान की अनुभूति होती है उन्होने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत शीर्ष संस्थान जैसे भूमि विकास बैक, होलसेल भण्डार, क्रय विक्रय सहकारी समिति एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यता हेतु कार्यक्रम पुरे जिले भर में चलाया जा रहा है। जिसके लिए कार्यकर्ताओ को दायित्व प्रदान किये गये है। इस अवसर पर जिला महामंत्री अभिषेक चोटिया, भण्डार चेयरमेन मोहनलाल गढ़वाल, सहकारिता आंदोलन सदस्यता अभियान के जिला सहसंयोजक योगेश तिवाड़ी, भाजयुमो जिला महामंत्री जयपाल सिंह टकणेत सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

चूरू के रतनगढ़ में संगठन सृजन अभियान की पहली बैठक आयोजित

रतनगढ़ (रॉयल पत्रिका)। एआईसीसी पर्यवेक्षक सुभाष चौपड़ा ने की जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से चर्चा कर की राय सुमारी। केंद्रीय पर्यवेक्षक के साथ पीसीसी पर्यवेक्षक हाकम अली खान, डॉ. राजेंद्र मुंड, रामनिवास इत्यादि ने भी की राय सुमारी। एनएसयुआई एवं युवा कांग्रेस में राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राष्ट्रीय संयोजक रह चुके तथा वर्तमान में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बीकानेर प्रभारी एडवोकेट सद्दाम हुसैन ने चूरू जिला कांग्रेस कमेटी में जिला अध्यक्ष पद पर की दावेदारी पेश। एआईसीसी की ओर से चूरू आएं केन्द्रीय पर्यवेक्षक सुभाष चौपड़ा के समक्ष की दावेदारी पेश। आज दावेदारी पेश करने वाले दावेदारों में एडवोकेट सद्दाम हुसैन सब से कम आयु तथा सर्वाधिक शैक्षणिक योग्यता वाले हैं दावेदार। एडवोकेट सद्दाम हुसैन अब तक पांच युजी ओर पांच पीजी कर चुके हैं तथा आगे की पढ़ाई अभी भी निरन्तर जारी। एडवोकेट सद्दाम हुसैन एनएसयुआई एवं युवा कांग्रेस में राष्ट्रीय पदाधिकारी के साथ-साथ रह चुके हैं मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पूर्वी उत्तरप्रदेश राज्य के रह चुके हैं। प्रदेश प्रभारी वर्ष 2023 में तत्कालीन गहलोत सरकार ने किया था राज्य स्तरीय युवा पुरस्कार से सम्मानित तथा इससे पूर्व भी हो चुके हैं राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय कार्य करने पर सम्मानित।

बठिंडा वाले जिन्देशाह मदार के गद्दीनशीं पीर हाजी अनवार अली शाह की वफात

चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय पर हाजन मस्जिद के पास बठिंडा वाले जिन्देशाह मदार सिल शिले के पीर हाजी अनवार अली शाह के वफात होने पर, उनके आस्ताने गद्दी अली मोहम्मद शाह पर चूरू जिले भर से उनके चाहने वालों ने बैठक में मगफिरत के लिए दुवाएं की गई। आस्ताना के सदर ज़ाकिर झरियावाला ने बताया कि पीर हाजी अनवार अली शाह, जिन्देशाह मदारिया गद्दी पर आसीन थे, आपके चाहने वालों देश व प्रदेश ही नहीं विदेशों में उनके मुरीद थे(शिष्य) झरियावाला ने बताया दुवाएं कुरआन खानी में व्यवस्था लंगर की महाराष्ट्र हज कमेटी सदस्य क़ाज़ी शकील उनके मुरीद की तरफ़ से की गई। इस अवसर पर आलिम, मौलाना लियाकत अली, बगड़ दरगाह पीर दीन मोहम्मद शाह, बाबा शमशुद्दीन, बाबा मुस्लिम, चमन भींचर, काज़ी अल्ताफ़ हुसैन, काज़ी शकील, कॉम काजियान सदर संजय भाटी, चूरू जिला अंजुमन अल शबाब जमील चौहान, आमीन दिलावर खानी, धोलू रमजान खान, हिदायत खान, मुंशी खान, मोहम्मद सलीम, चांद नूर खोखर, हाजी फैजलहक, इदरीश खान नारू, एडवोकेट इकबाल, तौफीक, उस्मानगनी खान, कादरी साहब, आदि ने शिरकत की कुराने पाक की तिलावत की गई ओर दुवाएं की गई ।

“आज की बचत, कल का भविष्य”

-आरयूआईडीपी ने विद्यार्थियों को सिखाए जल संरक्षण के गुर

बूंदी (रॉयल पत्रिका)। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) द्वारा अपने सामुदायिक जागरूकता एवं जन सहभागिता कार्यक्रम के तहत जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। आरयूआईडपी की अधिशाषी अभियंता, सोनम शर्मा के कुशल निर्देशन में, शुक्रवार को युवा पीढ़ी को पानी के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, गणेश बाग में एक प्रेरणादायक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कैप-आरयूआईडीपी के प्रतिनिधि सचिन मुदगल ने विद्यार्थियों को जल संरक्षण के महत्व पर बहुमूल्य जानकारी दी। उन्होंने जोर देकर कहा, “आवश्यकतानुसार ही जल का उपयोग करें और पानी की एक-एक बूंद बचाएं, क्योंकि ‘आज की बचत कल का भविष्य है’।” उनके शब्दों ने विद्यार्थियों को जल के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए प्रेरित किया।

घरेलू उपायों से संभव है बड़ा बदलाव-

इसी क्रम में, सोशल सेफगार्ड विशेषज्ञ नरेश महावर ने जल संरक्षण को वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत बताया। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे पानी का व्यर्थ बहाव रोकें और इसका सदुपयोग करें। महावर ने दैनिक जीवन में अपनाए जा सकने वाले सरल घरेलू उपायों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंवने बताया कि ब्रश करते समय या दाढ़ी बनाते समय नल बंद रखें। बर्तन धोते समय सिंक में लगातार नल न चलाएं। गाड़ी धोने के लिए पाइप की जगह बाल्टी और मग का प्रयोग करें, जिससे काफी पानी बचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने परियोजना से संबंधित किसी भी शिकायत अथवा सुझाव के लिए टोल-फ्री नंबर की जानकारी भी साझा की। इस दौरान एसओटी टीम की बबीता तथा विद्यालय के स्टाफ सदस्य शिवराज शर्मा, रवि कुमार गौतम, रितेश कुमार जैन, सीमा मीना और कमलेश बाई मीना सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यक्रम की सफलता में अपना योगदान दिया। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए न केवल जानकारीपूर्ण था, बल्कि उन्हें जल के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने में भी सफल रहा।

कन्नौज ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल में जिला कलक्टर ने की जनसुनवाई

चित्तौड़गढ़ (रॉयल पत्रिका)। भदेसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कन्नौज के मुख्यालय पर गुरुवार रात्रि को जिला कलक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल एवं जनसुनवाई का आयोजन किया गया। रात्रि चौपाल में कुल 26 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा शेष प्रकरणों को 7 से 10 दिन में समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जनसुनवाई से पूर्व जिला कलक्टर ने विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मेधावी छात्र-छात्राओं एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्रा आरती आचार्य ने जिला कलक्टर से संवाद करते हुए पूछा कि वे कलक्टर के पद तक कैसे पहुंचे। इस पर रंजन ने सभी विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि “मोबाइल पर समय कम दें, समाचार पत्र पढ़ें, विषयों की गहराई से पढ़ाई करें, निरंतर प्रयास से ही सफलता की मंज़िल आसान होती है।” विद्यालय की छात्रा ने जिला कलक्टर को फोटो

पेंटिंग बनाकर भेट की।

रात्रि चौपाल के दौरान जिला कलक्टर ने एक-एक परिवादी की समस्याओं को-

तल्लीनता पूर्वक सुना और तत्काल समाधान के निर्देश दिए। ग्रामीणों द्वारा पानी की सप्लाई 48 घंटे में मिलने की शिकायत पर, जिला कलक्टर ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव में प्रतिदिन पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। खेल मैदान में पानी भराव की शिकायत पर जिला कलक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को मौके पर निरीक्षण कर डीएमएफटी मद से मैदान सुधार कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी भूमि को आबादी क्षेत्र में कन्वर्जन की मांग पर, उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिला कलक्टर ने रसद अधिकारी से गांव खाद्य सुरक्षा एवं गैस कनेक्शन एवं एनएफएसए के बारे में जानकारी ली। चौपाल के दौरान बिजली कनेक्शन देने, विद्यालय में चार दीवारी बनाने, शौचालय निर्माण, सांवलियाजी आसवरा रोड़ मार्ग की मरम्मत करने, भदेसर मे भेरू जी मन्दिर के पास अन्नपूर्णा भोजनालय प्रारंभ करने, रास्तों से अतिक्रमण हटाने तथा गांव में जल निकासी सुधार जैसी जनसमस्याओं पर भी जिला कलक्टर ने संबंधित विभागों को तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

क्रय विक्रय सहकारी समिति बीकानेर और कोलायत में हुआ आस्तियों एवं दायित्वों का विभाजन

बीकानेर (रॉयल पत्रिका)। सहकार विभाग द्वारा संचालित बीकानेर कोलायत तहसील क्रय विक्रय सहकारी समिति की आमसभा की बैठक शुक्रवार को कृषि उपज मण्डी में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता हरिराम सियाग द्वारा की गई। सहकारी समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उमाकांत व्यास ने बताया कि आमसभा में कोलायत क्रय विक्रय सहकारी समिति कोलायत के गठन उपरान्त आस्तियों एवं दायित्वों का विभाजन किया गया। साथ ही समिति के नाम का संशोधन करते हुए बीकानेर क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड रखा गया। इसके अतिरिक्त समिति में नवीन व्यवसाय खोले जाने, न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद कार्य विभागीय निर्देशानुसार करवाए जाने के प्रस्तावों पर सहमति प्राप्त की गई। साथ ही विभागीय निर्देशानुसार सहकार सदस्यता अभियान के तहत नवीन सदस्यों ने सदस्यता प्राप्त की। बैठक में समिति कर्मचारी ललित रामावत, अजहरूद्दीन, प्रकाश छींपा, गणेश सोनी, योगेश कुमार बंशीवाल एवं रमेश सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

नर्मदा नहर परियोजना की जल वितरण समिति की बैठक सम्पन्न

-टेल लाइन पर किसानों को मिले पर्याप्त पानी-के.के.विश्नोई

जालोर (रॉयल पत्रिका)। नर्मदा नहर परियोजना में रबी फसल वर्ष 2025 -26 की अवधि में जल प्रवाहित करने के लिए जल वितरण समिति की बैठक राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री के.के.विश्नोई व बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल की उपस्थिति तथा संभागीय आयुक्त जोधपुर डॉ. प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को नर्मदा नहर परियोजना के विश्राम गृह सांचौर में आयोजित की गई। बैठक में राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के. विश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आमजन के उत्थान एवं विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि नर्मदा नहरी तंत्र को विकसित, आधुनिक एवं सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा बजट का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारी को

निर्देशित करते हुए कहा कि नर्मदा नहर परियोजना के माध्यम से हेड क्षेत्र जे साथ ही टेल कमांड क्षेत्र में आने वाले किसानों को भी कृषि एवं सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा पानी पहुंचाया जाए। बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल जल वितरण की वर्तमान स्थिति एवं सामने आ रही चुनौतियों, जल के समुचित वितरण व किसानों को समय पर जल उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने की बात कही। बैठक में नर्मदा बेसिन के सरदार सरोवर बाँध में वर्ष 2025-26 के लिए पानी की उपलब्धता, रबी फसल में परियोजना में स्वीकृत सिंचाई तीव्रता, उपलब्ध पानी से आगामी रबी सिंचाई के लिए माह नवम्बर 2025 से मार्च 2026 तक नहरों में प्रवाहित किये जाने वाले जल की मात्रा एवं रेगुलेशन कार्यक्रम के निर्धारण,. अवैध पानी चोरी रोकथाम, निर्बाध विद्दत आपूर्ति, वाली छोटी नहरों, माइनर्स, सब माइनरो सील्ट व गाद हटाने को लेकर चर्चा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

पोलीटेक्निक कॉलेज में शुरु हुआ ग्रेन इंडस्ट्री एक्सपो

-विधायक व्यास और जिला कलक्टर सहित अन्य अतिथियों ने की शुरुआत

बीकानेर, 10 अक्टूबर। तीन दिवसीय ग्रेन इंडस्ट्री एक्सपो का शुभारम्भ शुक्रवार को पोलीटेक्निक कॉलेज मैदान में हुआ। शुभारम्भ समारोह में बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास, जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेन्द्र वर्मा, ब्रह्म गायत्री सेवाश्रम के अधिष्ठाता रामेश्वरानंद तथा जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पचीसिया मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक जेठानंद व्यास ने कहा कि बीकानेर में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसमें परम्परागत तरीके के साथ नई तकनीकों का समावेश होगा तो अच्छे परिणाम आएंगे। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में बनी इन अत्याधुनिक मशीनों से पैकेजिंग, मूल्य संवर्धन और पैकेजिंग को नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय उद्यमी इनका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जिला कलक्टर ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जिले के औद्योगिक विकास की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। राइजिंग राजस्थान जैसे आयोजन ने इसे और अधिक गति दी है। उन्होंने कहा कि बीकानेर में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को देखते हुए ऐसे आयोजन

समय-समय पर होने चाहिए तथा उद्यमियों द्वारा इनका लाभ लेना चाहिए। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि उत्पादन के साथ उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखना भी जरूरी है। अत्याधुनिक मशीनें इस दिशा में भी महत्वपूर्ण रहेंगी। रामेश्वरानंद ने कहा कि खेतों में कृषि कार्य करने से लेकर इनकी पैकेजिंग तथा मार्केटिंग से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को लाभ हो, इसके लिए अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना जरूरी है। बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पचीसिया ने बताया कि बीकानेर फूड इंडस्ट्री का हब है। यहां मेगा फूड पार्क और गैस पाइपलाइन मंजूर होने के बाद बड़ी कंपनिया बीकानेर का रुख कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बीकानेर दाल मील एसोसिएशन के सहयोग से दूसरी बार हो रहे इस आयोजन का उद्यमियों को लाभ मिलेगा। दाल मील एसोसिएशन के अध्यक्ष जय किशन अग्रवाल ने बताया कि तीन दिवसीय एक्सपो में पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सहित विभिन्न प्रदेशों के मशीनरी निर्माताओं की 60 स्टॉल्स लगाई गई हैं। इसका उद्देश्य बीकानेर के उद्यमियों को अत्याधुनिक तकनीक से रूबरू करवाना है। बीकानेर दाल मिल्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजकुमार पचीसिया ने बताया कि मेले, भारतीय संस्कृति में व्यापार, वाणिज्य और विपणन की प्राचीन व्यवस्था है और आज के आधुनिक युग में भी यह प्रासंगिक हैं। इवेंट डायरेक्टर बृजलाल भारद्वाज एवं पवन भारद्वाज ने बताया कि 10 से 12 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले ग्रेन इंडस्ट्री एक्सपो में मशीनरी निर्माता कंपनियों द्वारा अनाज, दाल, तेल, चावल, मसाले, पोहा एवं मूंगफली दानों की प्रोसेसिंग मशीनों को प्रदर्शित किया गया है।

सफलता की कहानी नियम 157 के तहत मिले आवासीय पटटे

भीलवाड़ा (रॉयल पत्रिका)। ग्रामीण सेवा शिविर केम्प ग्राम पंचायत धनोप में आयोजित किया गया। उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां ओमप्रकाश, तहसीलदार फूलियाकलां रामदेव धाकड एवं प्रशासक, ग्राम पंचायत धनोप, रिंकु देवी वैष्णव के दिशा-निर्देशन में 15 विभागों ने आमजन का कार्य सम्पादित किया और मौके पर ही आमजन को राहत पहुचाई। शिविर के दौरान संजू देवी पत्नि दुर्गेश गर्ग, महावीर पुत्र उगमा कलाल, सुखी देवी पत्नि राजेन्द्र सेन, निवासी ग्राम धनोप तहसील फूलियाकलां को शिविर मे ही नियम 157 के तहत पुश्तैनी पटटे वितरित कर प्रार्थियों को राहत प्रदान की और वर्षो पुरानी समस्या का मौके पर ही समाधान किया। इससे प्रार्थियों ने प्रसन्नता व्यक्त की और राज्य सरकार तथा पूरे प्रशासन को धन्यवाद दिया। इस प्रकार ग्रामीण सेवा शिविर ग्रामीणजनों को उनके अधिकार दिलाने में सफल हुआ तथा यह केम्प उनके लिए वरदान साबित हुआ।

आरओ और एआरओ के लिए ऑनलाइन मूल्यांकन एवं शंका समाधान सत्र आयोजित

श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा आम चुनाव एवं उपचुनावों के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी के लिए 9 और 10 अक्टूबर 2025 को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नामांकन प्रक्रिया से संबंधित ऑनलाइन मूल्यांकन एवं शंका समाधान सत्र शामिल था। आयोग के अनुसार इस प्रशिक्षण में कुल 243 आरओ और 1418 एआरओ ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि आयोग, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 21 और 24 के तहत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आरओ एवं एआरओ को नामित करता है, ताकि चुनाव प्रक्रिया विधि अनुसार और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो सके। राजस्थान के लिए अंता विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी को इन ऑनलाइन सत्रों में नामांकन प्रक्रियाए योग्यता और अयोग्यता से जुड़ी प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनरों द्वारा आरओ और एआरओ की शंकाओं का समाधान किया गया ताकि चुनावों का संचालन सुचारू रूप से हो सके। आयोग ने सीईओए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और आरओ के लिए ईसीआईनेट के प्रेसाइडिंग ऑफिसर मॉड्यूल पर भी ऑनलाइन ब्रीफिंग सत्र आयोजित किया। इस मॉड्यूल के माध्यम से पीठासीन अधिकारी दो-दो घंटे के अंतराल पर मतदान प्रतिशत की जानकारी ECINET ऐप पर अपलोड करेंगे, जिससे वास्तविक समय में मतदान की स्थिति का आकलन संभव हो सकेगा।

प्रमुख शासन सचिव ने किया शहरी सेवा शिविर का औचक निरीक्षण

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की प्रमुख शासन सचिव देवाशीष पृष्टि ने शुक्रवार को अजमेर विकास प्राधिकरण परिसर में राज्य सरकार द्वारा आयोजित किये जा रहे शहरी सेवा शिविर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रमुख शासन सचिव देवाशीष पृष्टि ने प्राधिकरण द्वारा शिविर के दौरान किए जा रहे कार्यों तथा लीज-डीड, नामान्तरण, भवन निर्माण स्वीकृति, उप-विभाजन एवं संयुक्तिकरण में छूटों व दरों, प्रक्रिया एवं लम्बित प्रकरणों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। शिविर में उपस्थित आमजन, लाभार्थियों एवं आवेदकों से संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के लिए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये। उन्होंने प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति का आंकलन

करते हुए राज्यांश की समयबद्ध प्रदायगी, ई-ग्रास प्रणाली एवं लीज वसूली के संबंध में प्राधिकरण के प्रयासों की सराहना की। इसी क्रम में प्रमुख शासन सचिव ने प्राधिकरण द्वारा सम्पादित किये जा रहे विभिन्न विकास कार्यों, बजट घोषणा के कार्यों की समीक्षा की। राज्य सरकार के निर्देशानुसार दीपावली पर्व से पूर्व सभी पेचवर्क, सौन्दर्यकरण, विद्तीकरण व साज-सज्जा के कार्य अनिवार्यतः पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। शिविर के दौरान निष्पादित लीज-डीड, भवन निर्माण स्वीकृति तथा उप-विभाजन आदेशों का लाभार्थियों को मौके पर ही वितरण कर प्राधिकरण द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। आमजन को राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस शहरी सेवा शिविरों में प्रदत्त छूट एवं राहत का लाभ प्राप्त करने की अपील की। इस अवसर पर प्राधिकरण की आयुक्त नित्या के. एवं समस्त अधिकारीगण उपस्थित रहे।

माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार ग्रामीण-शहरी सेवा शिविरों के जरिए आमजन तक पहुंचाएं राहत

-समीक्षा बैठक में बीकानेर संभागीय आयुक्त ने दिए निर्देश

श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। बीकानेर संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ग्रामीण सेवा शिविर, शहरी सेवा शिविर और फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने जिले में आयोजित हो रहे ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से आम जन तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में संभागीय आयुक्त ने जिले में अब तक आयोजित हुए ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि शिविरों के माध्यम से आमजन को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाया जाना सुनिश्चित करें। समस्त विभागों के अधिकारी शिविर में मौजूद रहकर आमजन की समस्याओं को सुनें और यथासंभव उनका निस्तारण करें। ग्रामीणों के जो काम मौके पर हो सकते हैं, उन्हें पूर्ण करवाते हुए राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार ग्रामीण

एवं शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से आमजन तक राहत पहुंचाई जाए। शिविरों का आयोजन और इनके माध्यम से आमजन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों के दौरान ज्यादा से ज्यादा पट्टे वितरित करते हुए वंचितों को जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभन्वित करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान स्वास्थ्य, राजस्व, कृषि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, बिजली, नगर परिषद, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सहित समस्त विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए संभागीय आयुक्त ने कहा कि समस्त विभागीय अधिकारी पूर्ण संवेदनशीलता के साथ आमजन की समस्याओं का निस्तारण करें। शिविरों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जिन विभागों की प्रगति कमजोर है, वे आवश्यक सुधार करें। इस दौरान मिनी किट वितरण, खाद और बीजों की उपलब्धता पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उर्वरकों का वितरण समान रूप से सुनिश्चित किया जाए। बैठक में संभागीय आयुक्त द्वारा पालनहार योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, खाद्य सुरक्षा योजना, गिव अप अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्वानिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, जल जीवन मिशन, पंच गौरव और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लेकर भी निर्देश दिए गए।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त रही सीटों पर प्रवेश की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर तक बढ़ाई

-प्रवेश से वंचित अभ्यर्थियों के लिए एक और सुनहरा अवसर- जी. एस. नायक

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। महिला एवं पुरुष राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित समस्त निजी एवं राजकीय संस्थानों में रिक्त रही सीटों पर प्रवेश के लिए एकीकृत एसएसओ पोर्टल अथवा ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि डीजीटीनि दिल्ली द्वारा 16 अक्टूबर प्रातः 11.30 बजे तक बढ़ाई गई है। संस्थान के उप निदेशक अनिल शर्मा ने बताया कि आवेदन पत्र का प्रिंट मय योग्यता संबंधित दस्तावेजों की फोटो प्रति के व्यक्तिशः इच्छुक संस्थान में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक है। महिला संस्थान के सहायक निदेशक शैलेन्द्र माथुर के अनुसार संस्थान में प्राप्त आवेदन पत्रों की संस्थान स्तर पर नियमानुसार मेरिट जारी कर नोटिस बोर्ड पर लगाने की तिथि 16 अक्टूबर सायं 5 बजे है। महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा की छूट है। संभाग के संयुक्त निदेशक जी. एस. नायक ने आह्वान किया है कि प्रवेश से वंचित रहे अभ्यर्थियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। इससे अधिकाधिक संख्या में आवेदन करें। उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे मेरिट के आधार पर समस्त श्रेणीयों के प्रवेश आवेदित संस्थान में किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज, निर्धारित फीस एवं कोशन मनी सहित इसके लिए स्वयं उपस्थित होना होगा। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शुल्क माफ है। आवेदित संस्थान के समस्त व्यवसायों में रिक्त रही सीटों पर मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रदान किए जाएंगे। उपाचार्य गामिनी शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए संस्थान के प्रत्येक व्यवसाय की विस्तृत जानकारी एवं रिक्त स्थानों को संस्थान में प्रदर्शित किया गया है।

विश्वकर्मा पेंशन योजना बनी बुढ़ापे का सहारा

-ग्रामीण सेवा शिविर में मिला सम्मानजनक भविष्य का संबल

जालोर (रॉयल पत्रिका)। आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ उनके द्वार तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर-2025 आम लोगों के लिए आशा का माध्यम बन रहे हैं। जालेर तहसील की आंवलोज ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को तहसीलदार दिग्विजय सिंह, शिविर प्रभारी रेशाराम सुन्देशा व राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के वरिष्ठ सहायक सुजाराम ने पेंशन स्वीकृति पत्र सौंपे। इसी प्रकार विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत जसवंतपुरा पंचायत समिति की दांतलावास ग्राम पंचायत में आयोजित चेतना देवी पत्नी मोहनलाल तथा सायला पंचायत समिति की बैरठ ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में धीराराम पुत्र भलाजी को पॉलिसी प्रदान कर लाभांवित किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें ग्रामीण सेवा शिविर में पेंशन योजना के लिए आवेदन करने और सत्यापन

की पूरी प्रक्रिया पूरी कराने में बड़ी सुविधा मिली। आवेदन स्वीकृत होने के बाद उन्हें यह जानकर अत्यंत खुशी हुई कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उन्हें प्रतिमाह 3000 रूपए की राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होगी।

बेसिक पेंटर कोर्स समाज के बदलते परिवेश में महिलाऐं आर्थिक रूप से होगी सशक्त

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजनान्तर्गत वर्ष 2025-2026 में एशियन पेंट्स कलर अकेडमी के सौजन्य से बेसिक पेंटर कोर्स(बीपीसी) जिले की अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घूघरा में 6 से 11 अक्टूबर तक महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वरोजान्मुख भावना को विकसित करने के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। महिला अधिकारिता विभाग की उप निदेशक मेघा रतन ने बताया कि महिलाओं को समाज के बदलते परिवेश में आत्मनिर्भर होना आवश्यक है।

एकता कपूर ने अभिनेताओं से सार्वजनिक रूप से

मांगी माफी

टीवी इंडस्ट्री की क्वीन एकता कपूर ने एक वीडियो जारी करते हुए उन सभी अभिनेताओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है, जिनकी उन्होंने वर्षों से आलोचना की है। इसकी वजह भी सामने आ गई है। टेलीविजन और फिल्म निर्माता एकता कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी सेक्शन पर एक वीडियो अपलोड किया। इसमें एकता कहती हैं, विज्ञापनों में अपने हालिया विवाद के बाद मैं उन सभी अभिनेताओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहती हूं, जिनसे मैंने कहा था, आपका अभिनय उम्मीद के मुताबिक नहीं था। मुझे सच में खेद है। दरअसल, हाल ही में एकता कपूर कई तरह के उत्पादों के विज्ञापनों में नजर आई थीं। इनमें एक विज्ञापन में उन्होंने दावा किया था, 'मैंने दुनिया को के-ड्रामा दिया', जो उनके मशहूर टीवी सीरियल्स 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', 'कहानी घर घर की', 'कुसुम' और 'पवित्र रिश्ता' की तरफ इशारा था। इनमें से कुछ में वह कहती दिखी थीं, कुछ कलाकार तो ऐसे थे, जो एक्टिंग तक नहीं करना जानते थे। इसके चलते एकता कपूर की खूब आलोचना हुई थी। हालांकि, यह विज्ञापन अब सोशल मीडिया से हटा लिया गया है, लेकिन खुद की किरकिरी होते देख एकता कपूर ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली। दूसरी तरफ एकता कपूर की फिल्म 'कटहल' को हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के दौरान सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया था। इस फिल्म को गुनीत मोंगा और एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में सान्या मल्होत्रा, अनंत जोशी, विजय राज और राजपाल यादव जैसे सितारे हैं। इस फिल्म को यशोवर्धन मिश्रा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी अशोक मिश्रा ने लिखी है। राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने के बाद एकता कपूर ने एक पोस्ट में लिखा था, राष्ट्रीय पुरस्कार और कटहल की जीत का जश्न मनाना बालाजी की पूरी टीम के लिए एक जादुई पल है। यह कहानी प्रामाणिक, अनोखे भारतीय आख्यानों पर प्रकाश डालने के लिए रची गई थी और आज की मान्यता इस सफर को अविस्मरणीय बनाती है।

ऋषभ शेट्टी की

कांतारा चैप्टर 1 ने हिंदी में भी कमाए 100 करोड़

● साउथ की यह फिल्में भी कर चुकीं ऐसा ही कमाल

बॉक्स ऑफिस पर ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने अब तक कमाल का प्रदर्शन किया है। फिल्म ने हिंदी वर्जन ने भी अब 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।

साउथ सिनेमा का जलवा एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर छा गया है। ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने इतिहास रच दिया है। फिल्म के हिंदी वर्जन ने न सिर्फ 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया, बल्कि यह उपलब्धि हासिल करने वाली साउथ की केवल 12वीं फिल्म बन गई है।

हिंदी में भी 100 करोड़ पार हुई फिल्म: ऋषभ शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बुधवार को लगभग 8.5 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसका कुल हिंदी कलेक्शन 102 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का हिंदी वर्जन अन्य भाषाओं की तुलना में सबसे तेजी से 100 करोड़ क्लब में शामिल हुआ। कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम संस्करणों को जोड़ें तो फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 316 करोड़ रुपये हो चुका है। यह साबित करता है कि 'कांतारा चैप्टर 1' सिर्फ एक रीजनल फिल्म नहीं, बल्कि एक पैन इंडिया फिनॉमिना बन चुकी है।

वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी कब्जा:

'कांतारा चैप्टर 1' का बजट लगभग 125 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। मंगलवार तक इसका ग्लोबल कलेक्शन 427 करोड़ रुपये था, जो बुधवार को बढ़कर 450 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।

साउथ की वो 12 फिल्में जिनके हिंदी वर्जन ने मचाया धमाल

1. बाहुबली: द बिगिनिंग (2015)
एस.एस. राजामौली के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने हिंदी बेल्ट में 118.7 करोड़ रुपये की कमाई की थी। प्रभास, राणा दग्गुबती और तमन्ना भाटिया के अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था।

2. पुष्पा: द राइज (2021)
अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने हिंदी में 108.26 करोड़ रुपये की कमाई की। यह फिल्म आम जनता के बीच एक ट्रेंड बन गई थी – झुकेगा नहीं।

3. साहो: (2019)
प्रभास और श्रद्धा कपूर की यह फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 142.95 करोड़ रुपये लेकर आई थी।

4. सलार पार्ट 1: सीजफायर (2023)
प्रशांत नील के निर्देशन में बनी इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने 153.84 करोड़ रुपये कमाए।

सान्या मल्होत्रा ने दिखाया सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का फनसाइड

अभिनेत्री और स्टार परफॉर्मर सान्या मल्होत्रा ने फैंस को पर्दे के पीछे की वह मस्ती दिखाई है, जिसकी हमें ज़रूरत तो थी, लेकिन हमने सोची नहीं थी! हाल ही में उन्होंने सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के सेट से एक मज़ेदार बीटीएस मोमेंट्स शेयर की है, और यह फैन्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। हंसी-मज़ाक से भरे ब्रेक्स से लेकर अनपेक्षित और सच्चे पलों तक, सान्या की (बिहाइंड द सीन्स) फोटोज़ और वीडियोज़ का ये करूसल फिल्म की स्टारकास्ट के बीच की गर्मजोशी और दोस्ती को बखूबी दर्शाता है। चाहे वो एक छोटा सा मज़ाक हो, शूटिंग के दौरान हुई किसी गलती पर साझा हँसी, या एक-दूसरे के प्रति सच्चा सम्मान, हर पल में सब के बीच की दोस्ती साफ़ दिखाई देती है। सान्या की ऊर्जा पूरे माहौल को हल्का और खुशनुमा बना देती है, जिससे लंबे शूटिंग शेड्यूल भी आसान लगते हैं। फैंस ने कमेंट सेक्शन में तुरंत प्रतिक्रिया की बाढ़ ला दी – सभी को पर्दे के पीछे की ये झलकियाँ बेहद पसंद आईं। यह याद दिलाने वाला है कि बेहतरीन कहानी सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं, बल्कि उसके पीछे भी बनती है। मस्ती भरे पलों से लेकर दिल को छू लेने वाली बातों तक, सान्या मल्होत्रा अपने प्रशंसकों को एक बेहतरीन तोहफ़ा दे रही हैं - सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की खुशनुमा दुनिया की एक झलक, जहां हर मुस्कान, हर हँसी और हर बीटीएस मोमेंट यादगार बन जाता है। हाल ही में फिल्म 'कटहल' के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने और 'मिसेज़' में सराहे गए परफॉर्मेंस के बाद, सान्या का करियर एक दुर्लभ संतुलन दिखाता है – जहां कला और व्यवसाय दोनों साथ चलते हैं।

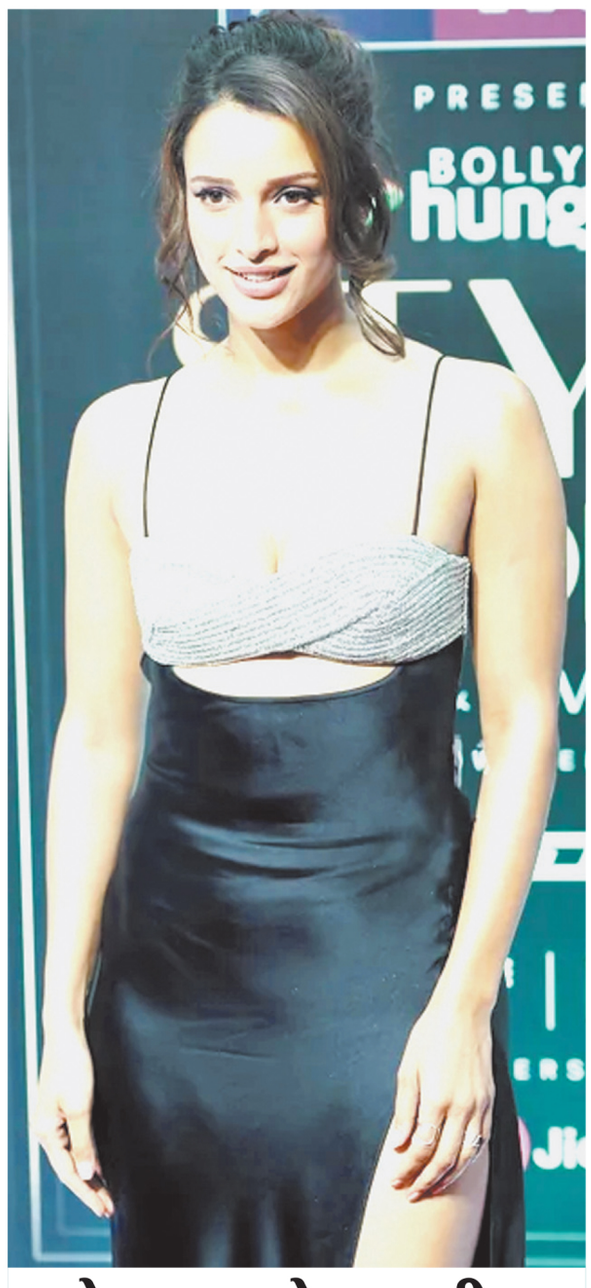

वेटरन एक्ट्रेस परवीन बॉबी की बायोपिक सीरीज में दिखेंगी तृप्ति

तृप्ति डिमरी के पास इन दिनों कई प्रोजेक्ट्स हैं। इस बीच अब उनके नए प्रोजेक्ट को लेकर दिलचस्प खबर सामने आ रही है। तृप्ति के हाथ एक और बड़ा प्रोजेक्ट लगा है। तृप्ति को एक बायोग्राफिकल सीरीज में वेटरन एक्ट्रेस परवीन बॉबी की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस नेटफ्लिक्स सीरीज का निर्माण जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है, जिसमें द स्काई इज पिंक की निर्देशक शोनाली बोस इस प्रोजेक्ट का निर्देशन करेंगी। एक सूत्र ने बताया कि तृप्ति की डेट्स तय हो गई हैं। निर्देशक शोनाली बोस और उनकी टीम इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही हैं। बता दें कि तृप्ति के पास आने वाले समय में कई रोमांचक फिल्में हैं। उन्होंने अपने बहुमुखी अभिनय से खुद को एक स्टार के रूप में साबित किया है और अब वह एक बार फिर ओटीटी स्पेस में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं। इस बायोपिक के अलावा तृप्ति, विशाल भारद्वाज की अगली फिल्म का भी हिस्सा हैं, जिसमें वह शाहिद कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। इसे साजिद नाडियाडवाला द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

सारा खान ने की दूसरी शादी

एक्टर-प्रोड्यूसर कृष पाठक संग लिए सात फेरे

'बिदाई' और 'बिग बॉस' फेम एक्ट्रेस सारा खान फिर से शादी के बंधन में बंध गई हैं। एक्ट्रेस ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड एक्टर-प्रोड्यूसर कृष पाठक संग रजिस्टर्ड मैरिज की है। दोनों ने 6 अक्टूबर को करीबियों के बीच अपनी शादी को रजिस्टर किया है। कपल अब दिसंबर में ग्रैंड वेडिंग सेलिब्रेशन करेगा। सारा ने इंस्टाग्राम पर शादी की खुशखबरी शेयर करते हुए कृष संग कई तस्वीरें शेयर की हैं। साथ ही एक भावुक नोट पोस्ट किया है। सारा ने लिखा- 'दो आस्थाएं। एक स्क्रिप्ट। असीम प्रेम। सिग्नेचर हो गए हैं। कुबूल है से सात फेरे तक इस दिसंबर का इंतजार है। दो दिल, दो संस्कृतियां हमेशा के लिए एक हो गईं। हमारी प्रेम कहानी एक ऐसे मिलन का गढ़ कर रही है, जहां आस्थाएं मिलती हैं, विभाजित नहीं होतीं। जब प्यार ही हेडलाइन बन जाए तो बाकी सब कुछ एक खूबसूरत कहानी बन जाता है। इसलिए हमें अपना आशीर्वाद

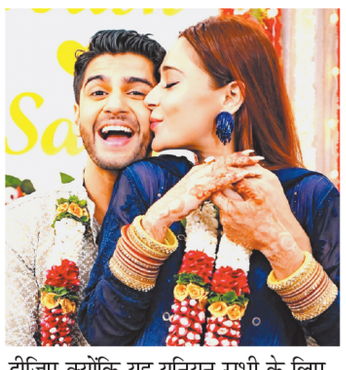

दीजिए क्योंकि यह यूनियन सभी के लिए है। सारा और कृष की शादी पर फैंस और सेलेब्स खूब बधाई दे रहे हैं। हाल ही में शादी के बंधन में बालिका वधू फेम एक्ट्रेस अविका गौर ने सारा को बधाई दी है। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने लिखा- 'ओह माय गॉड। माई बेबी...बधाई।' इसकेअलावा कपल को एक्ट्रेस आशका गोराडिया, किश्वर मर्चेंट, गायक अभिजीत सावंत ने भी बधाई दी है।

अक्षय बढ़ाएंगे 70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स की शोभा

मंच पर परफॉर्म करने के लिए हैं तैयार

70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स 2025 में शाहरुख खान, करण जौहर और मनीष पॉल होस्ट होंगे। इसके अलावा भी कई सितारे 11 अक्तूबर की शाम को रंगीन बनाएंगे। 70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स 2025 का आयोजन 11 अक्तूबर को गुजरात के अहमदाबाद में होने वाला है। इस ऐतिहासिक समारोह में भारतीय सिनेमा के कई सितारे मौजूद रहेंगे। सितारों से सजे इस कार्यक्रम में अक्षय कुमार भी एक धमाकेदार प्रस्तुति देने के लिए तैयार हैं।

क्या बोले अक्षय कुमार?

कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने पर अक्षय कुमार ने कहा फिल्मफेयर ने मुझे हर तरह से सम्मानित किया है। मैंने खलनायक, हास्य अभिनेता और कई अन्य भूमिकाओं के लिए पुरस्कार जीते हैं। द ब्लैक लेडी मेरे करियर की गवाह रही है। एक-एक भूमिका के साथ और फिल्मफेयर के 70वें वर्ष में मंच पर प्रस्तुति देना अद्भुत है। पुरस्कार समारोह में मेरी परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाइए!

एक्टर ने 9 महीने बाद बताया सारा सच, मां शर्मिला ने दी थी बड़ी सलाह

सैफ अली खान पर चाकू से हुआ था नकली हमला

सैफ अली खान ने काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो टू मच में खुद पर चाकू से हुए हमले का जिक्र किया है। आपबीती सुनाते हुए उन्होंने उन लोगों को भी जवाब दिया जो इस हमले और सर्जरी को नकली और फर्जी बता रहे थे।

सैफ अली खान पर इसी साल की शुरुआत में उनके घर में ही चाकू से जानलेवा हमला हुआ। 16 जनवरी की रात को हुई इस वारदात ने बॉलीवुड से लेकर पुलिस महकमे तक, हलचल मचा दी। सवाल सुरक्षा को लेकर उठने लगे। कथित तौर पर चोरी के इरादे से एक शख्स सैफ-करीना के घर में दाखिल हुआ था। सैफ अली खान से उसकी हाथापाई हुई, जिसमें बचने के लिए उस चोर ने एक्टर पर चाकू से वार कर दिया। यह वाकया अपने-आप में डरावना था, खासकर तब जब पता चला कि वह बदमाश सैफ-करीना के छोटे बेटे जेह के कमरे में दाखिल हुआ था। इस घटना के बाद लहूलुहान सैफ अस्पताल में भर्ती हुए, जहां सर्जरी के बाद उनके शरीर से चाकू का एक हिस्सा निकाला गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, जिसके बाद इस हमले पर ही सवाल उठने लगे। कई लोगों ने कहा कि यह पूरा मामला ही झूठा है, क्योंकि सर्जरी के बाद जब सैफ अस्पताल से घर लौटे तो वह फिट दिख रहे थे। अपने पैरों पर चल रहे थे। अब 9 महीने बाद सैफ अली खान ने खुद इस पर चुप्पी तोड़ी है।

काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो टू मच में सैफ अली खान ने खुलासा किया कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वह अपने पैरों पर चलते हुए घर क्यों लौटे। यह भी बताया कि उस घटना और सर्जरी के बाद उनकी जिंदगी किस तरह से बदली। सैफ ने शो में जहां उस पूरी घटना को विस्तार से बताया, वहीं काजोल और ट्विंकल ने कहा कि सैफ असल जिंदगी के हीरो हैं, जिन्होंने अपने परिवार और बेटे जेह की सुरक्षा को प्राथमिकता दी।

सैफ अली खान ने सुनाया वारदात की रात का पूरा किस्सा

सैफ अली खान ने शो में बताया, 'उस रात करीना बाहर गई हुई थीं। मैं, तैमूर और जेह, हमने ठीक तभी एक फिल्म खत्म की थी। हम सोने लगे गए। काफी रात हो गई थी, करीब 2 बज रहे थे। करीना के घर आने के बाद हमने थोड़ी बात की। तभी उधर से मेड आई और कहा कि जेह बाबा के कमरे में कोई है। उसके हाथ में चाकू है और बोल रहा है कि उसको पैसे चाहिए।

सैफ का खुलासा- जेह और उसकी नैनी को भी लगा था चाकू

सैफ अली खान ने आगे कहा, मैंने जैसे ही यह सुना, झटका लगा। मैं यह सुनते सुनते बिस्तर से नीचे उतर गया। मैं अंधेरे में जेह के कमरे की तरफ दौड़ा। मैंने देखा कि वह आदमी उसके बेड पर खड़ा था, उसके हाथ में चाकू था। शो में सैफ के साथ मेहमान बनकर पहुंचे अक्षय कुमार ने इस पर पूछा कि क्या वह हमलावर जेह की तरफ चाकू किए हुए था वह चाकू इस तरह हिला रहा था कि जेह और उसकी नैनी के कट भी लगा।

वह अंधेरे में पागलों की तरह चाकू चलाने लगा

खैर, सैफ ने घटना का जिक्र करते हुए आगे कहा, मुझे अंधेरे में लगा कि वह मुझसे छोटा है। मतलब कि उम्र में। मैं उसकी तरफ कूदा। बाद में जेह ने मुझसे कहा कि आपने गलती कर दी। आपको उसे लात-घूसा मारना चाहिए था। लेकिन मैं कूदा और हमारी हाथापाई होने लगी। वह पागलों की तरह बचने के लिए चाकू चलाने लगा और उसने मेरे शरीर पर कई जगह वार किए।

तैमूर ने कहा- मैं भी अस्पताल जाना चाहता हूं

सैफ ने बताया कि सही मायने में वह जेह की नैनी ही थी, जिसने उनहें बचाया। उसने बदमाश को पीछे धक्का दिया। लेकिन तब तक वह चाकू से कई वार कर चुका था। सैफ ने कहा, उसने मेरी रीढ़ पर वार किया था। तैमूर ने मुझसे पूछा कि अब्बा क्या आप मरने वाले हैं मैंने उससे कहा कि मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। एक्टर ने आगे बताया कि उस बदमाश के वहां से भागने के बाद करीना बच्चों को लेकर करिश्मा के घर जाने वाली थी। हमने एक ऑटो रिक्शा वाले को रोका। तब तैमूर ने कहा कि वह भी अस्पताल चलना चाहता है। सैफ कहते हैं, मैंने उस वक्त उसे देखा और मुझे अजीब शांति मिली।

सैफ के अस्पताल पहुंचने पर क्या हुआ

सैफ अली खान ने अस्पताल को याद करते हुए कहा, मैंने वहां पहुंचते ही एक लड़के से पूछा कि क्या वह मुझे स्ट्रेचर लाकर दे सकता है। उसने पूछा, व्हीलचेयर मैंने कहा कि नहीं, मुझे लगता कि मुझे स्ट्रेचर की जरूरत है। मैंने देखा कि वह उठ नहीं रहा था, तब मैंने उससे कहा कि मैं सैफ अली खान हूं, और यह मेडिकल इमरजेंसी है।

अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ, चलने में दर्द हो रहा था लेकिन...

आखरि में, सैफ अली खान ने उन आरोपों पर भी चुप्पी तोड़ी, जिसमें कहा गया कि हमला, और उसके सर्जरी यह सब झूठ था। एक्टर ने कहा, जब सबकुछ हो गया। मुझे बहुत तरह के सुझाव दिए गए। यह भी कि मुझे किस तरह बाहर जाना चाहिए। मीडिया बहुत उतावली हो रही थी। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। यह बहुत बुरा था। लेकिन मैं चल सकता था। उन्होंने सर्जरी के घाव की सिलाई की थी। चलने में दर्द हो रहा था। लेकिन मैं यह कर सकता था। व्हील चेयर की जरूरत नहीं थी।

मां शर्मिला टैगोर ने सैफ अली खान को दी थी सलाह

सैफ ने खुलासा किया कि मां शर्मिला टैगोर ने भी उनहें सलाह दी थी। मां ने कहा था कि पैदल चलने की बजाय व्हील चेयर पर जाओ। सैफ कहते हैं, मां ने व्हील चेयर पर अस्पताल से बाहर जाने की सलाह दी थी। लेकिन मैंने एक मैसेज देना चाहता था कि मैं अब ठीक हूं और मुझे मीडिया अटेंशन नहीं चाहिए थी। मैं बस फैंस और बाकी सब को यह संदेश देना चाहता था कि सब पहले से ठीक है और बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है।

साभार एजेंसी

शिवम दुबे का तूफानी शो, 62 गेंदों में शतक, एक ओवर में जड़े 4 छक्के

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में हैं. एशिया कप में भारत को खिताबी जीत दिलाने के बाद अब उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी बल्ले से कहर बरपा दिया है. पुणे में खेले गए मुंबई और महाराष्ट्र के बीच प्रैक्टिस मैच में दुबे ने ऐसा तूफानी प्रदर्शन किया कि गेंदबाजों के होश उड़ गए.

62 गेंदों में शतक, 9 छक्के और 5 चौके : मुंबई की ओर से खेलते हुए शिवम दुबे ने सिर्फ 62 गेंदों पर शतक ठोक दिया. उनकी पारी में 9 छक्के और 5 चौके शामिल रहे. जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की,विपक्षी टीम पूरी तरह बैकफुट पर आ गई. सबसे खास पल तब आया जब उन्होंने बाएं हाथ के स्पिनर हितेश वालुंज के एक ही ओवर में लगातार चार छक्के जड़ दिए. दुबे उस वक्त क्रीज पर आए जब मुंबई की टीम शुरुआती दो विकेट गंवाकर दबाव में थी. कप्तान हार्दिक तामोरे भी 24 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे. ऐसे में दुबे ने मोर्चा संभाला और 160 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए.

पृथ्वी शॉ ने जड़ा 181 रन, लेकिन विवाद में फंसे: इस मुकाबले में महाराष्ट्र की ओर से पृथ्वी शॉ ने भी बल्ले से आग उगली और शानदार 181 रन बनाए. हालांकि उनकी यह पारी बाद में विवादों में घिर गई. दरअसल, मैच के दौरान उनका झगड़ा मुंबई के खिलाड़ी मुशीर खान (सरफराज खान के छोटे भाई) से हो गया. जानकारी के मुताबिक, पृथ्वी शॉ आउट होने के बाद गुस्से में आ गए और उन्होंने मुशीर की ओर बैट उठाकर दौड़ लगा दी. मैदान पर माहौल गरम हो गया और दोनों खिलाड़ियों के बीच बहस बढ़ने लगी. अंपायर और टीम मैनेजमेंट ने बीच-बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया. इस घटना की जांच अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर को सौंपी गई है.

रणजी से पहले मिला चेतावनी का संदेश: रणजी ट्रॉफी शुरू होने से पहले खेला गया यह तीन दिवसीय अभ्यास मैच कई मायनों में चर्चा में रहा. एक तरफ शिवम दुबे की तूफानी बल्लेबाजी ने सभी का ध्यान खींचा, तो दूसरी ओर पृथ्वी शॉ के आक्रामक रवैये ने निराश किया. शिवम का ये फॉर्म भारतीय टीम के लिए बड़ा संकेत है कि ये ऑलराउंडर आने वाले सीजन में भी मैच जिताऊ खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.

कास्परोव ने आनंद पर शुरुआती बढ़त बनाई

तीसरी बाजी में भारत के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी को हराया

सेंट लुइस, एजेंसी। शतरंज के इतिहास के संभवत- सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कास्परोव ने 62 साल की उम्र में दिखाया कि 21 साल पहले संन्यास लेने के बावजूद उनमें अब भी काफी शतरंज बचा है। आनंद को भी मौके मिले लेकिन वह उनका फायदा उठाने में नाकाम रहे। भारत के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को क्लच शतरंज टूर्नामेंट की तीसरी बाजी में गैरी कास्परोव से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह महान खिलाड़ियों के बीच खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कास्परोव ने 2.5-1.5 की बढ़त बना ली। शतरंज के इतिहास के संभवत- सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कास्परोव ने 62 साल की उम्र में दिखाया कि 21 साल पहले संन्यास लेने के बावजूद उनमें अब भी काफी शतरंज बचा है। आनंद को भी मौके मिले लेकिन वह उनका फायदा उठाने में नाकाम रहे। शतरंज 960 प्रारूप के तहत रोजाना दो रैपिड और दो ब्लिट्ज मुकाबले होने हैं। दिन की शुरुआती दो बाजी ड्रॉ रहीं जिसके बाद कास्परोव ने तीसरी बाजी में आनंद को हराया। आनंद के पास बाजी को ड्रॉ कराने का मौका था लेकिन वह चूक गए।

इंडिया-वेस्टइंडीज टेस्ट

यशस्वी जयसवाल ने टेस्ट में ठोका सातवां शतक, शुभमन गिल और रवि शास्त्री का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा

नई दिल्ली, एजेंसी। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल ने शुक्रवार को दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में अपने टेस्ट करियर का सातवां टेस्ट शतक लगाया। इस शतक के साथ उन्होंने शुभमन गिल और रवि शास्त्री का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है जबकि एलेस्टेयर कुक और जावेद मियांदाद की एलीट लिस्ट में शामिल हो गए हैं। यहां यशस्वी ने खारी पियरे की पहली गेंद पर दो रन लेकर अपना सातवां शतक पूरा किया। उन्होंने 145 गेंदों में 16 चौके लगाते हुए अपना शतक बनाया। जायसवाल का सातवां टेस्ट शतक 24 साल की उम्र से पहले आया, केवल तीन खिलाड़ियों ने इससे अधिक शतक बनाए है। इस उम्र में ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन ने (12) शतक, सचिन तेंदुलकर ने (11) शतक, और गारफील्ड सोबर्स ने (9) शतक बनाने वालों में है। अब वह जावेद मियांदाद, ग्रीम स्मिथ, एलेस्टियर कुक और केन विलियमसन के साथ सात-सात शतक लगाने वाले क्लब में शामिल हो गए है।

● 23 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा टेस्ट शतक

12 - डोनाल्ड ब्रैडमैन (ऑस्ट्रेलिया), 26 पारियों में
11 - सचिन तेंदुलकर (भारत), 80 पारियों में
9 - गैरी सोबर्स (वेस्टइंडीज), 54 पारियों में
7 - यशस्वी जायसवाल (भारत), एलेस्टेयर कुक (इंग्लैंड), जावेद मियांदाद (पाकिस्तान), ग्रीम स्मिथ (दक्षिण अफ्रीका), केन विलियमसन (न्यूज़ीलैंड)

● 23 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा शतक

22 - सचिन तेंदुलकर (220 पारियां)
15 - विराट कोहली (119 पारियां)
8 - यशस्वी जायसवाल (71 पारियां)*
7 - रवि शास्त्री (110 पारी)
7 - शुभमन गिल (73 पारी)

फीफा 2026 विश्व कप क्वालीफायर:

स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स और डेनमार्क का शानदार प्रदर्शन

नई दिल्ली, एजेंसी। फीफा 2026 विश्व कप क्वालीफायर में स्कॉटलैंड ने ग्रीस पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज करते हुए अपनी संभावनाओं को मजबूत किया है। वहीं, नीदरलैंड्स, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया ने अपने प्रदर्शन से फैंस को प्रभावित किया। ग्रुप-सी के मुकाबले में हैम्पडेन पार्क में अपने पिछले दौरे में 3-0 से जीत हासिल करने वाली ग्रीस की टीम ने इस मैच में भी शानदार शुरुआत की। कोस्टास सिमिकास ने 62वें मिनट में गोल करते हुए ग्रीस को 1-0 से बढ़त दिलाई। हालांकि, ग्रीस की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। स्कॉटलैंड की ओर से रयान क्रिस्टी ने दो मिनट बाद (64वें मिनट) ही नजदीकी रेंज से गोल दागा। लुईस फर्ग्यूसन ने 80वें मिनट में गोल करते हुए स्कॉटलैंड को 2-1 से बढ़त दिला दी।

ग्रुप-सी के एक अन्य मैच में रासमस होजलुंड ने दो गोल दागकर डेनमार्क को हंगरी के खिलाफ 6-0 से जीत दिलाई। इसी के साथ जर्मनी ग्रुप में शीर्ष पर है, जबकि स्कॉटलैंड, ग्रीस और बेलारूस क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे पायदान पर मौजूद हैं। ग्रुप-जी में नीदरलैंड्स ने माल्टा को 4-0 से हराया। इस मुकाबले में कोडी गाकपो ने 12वें और 48वें मिनट में गोल दागे। विपक्षी टीम एक अदद गोल के लिए तरसती रह गई। नीदरलैंड की टीम इस ग्रुप में शीर्ष पर है। ग्रुप-एच में ऑस्ट्रिया ने सैन मैरिनो पर 10-0 से बड़ी जीत दर्ज की। इस मुकाबले में मार्को अर्नौटोविक ने चार (8वें मिनट, 47वें मिनट, 83वें और 84वें मिनट) गोल दागे। इसी के साथ मार्को अर्नौटोविक ऑस्ट्रिया के सर्वकालिक रिकॉर्ड स्कोरर बन गए हैं। मार्को ने इस देश के लिए 45 गोल दागे हैं। वह टोनी पोलस्टर से एक कदम आगे हैं। ग्रुप-एच में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर मौजूद है, जबकि सैन मैरिनो पांचवें पायदान पर है। इस ग्रुप में बोस्निया एंड हर्जेगोविना दूसरे, रोमानिया तीसरे और साइप्रस चौथे स्थान पर मौजूद हैं।

डब्ल्यूपीएल में पहली बार मेगा ऑक्शन, 5 प्लेयर्स रिटेन होंगे

● हर फ्रेंचाइजी के पास 15 करोड़ का बजट, राइट-टु-मैच कार्ड भी मिलेगा

नई दिल्ली, एजेंसी। विमेंस प्रीमियर लीग में पहली बार मेगा ऑक्शन होगा। ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी टीमें 5 प्लेयर्स को रिटेन कर सकेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, खिलाड़ियों को रिटेन करने की आखिरी तारिख 5 नवंबर है, जिसकी जानकारी टीमों को दे दी गई है। जबकि ऑक्शन की प्रक्रिया 25 से 29 नवंबर के बीच हो सकती है। गुरुवार को डब्ल्यूपीएल ने सभी फ्रेंचाइजी को एक ईमेल भेजे। इसमें कहा कि हर टीम ज्यादा से ज्यादा तीन कैप्ड भारतीय, दो विदेशी और दो अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी रिटेन कर सकती है। अगर कोई फ्रेंचाइजी पांच खिलाड़ियों को रिटेन करती है, तो उनमें कम से कम एक अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी होना अनिवार्य है। हर फ्रेंचाइजी के पास 15 करोड़ रुपए का बजट ऑक्शन के लिए हर फ्रेंचाइजी के पास 15 करोड़ रुपए का पर्स है। वहीं, रिटेंशन स्लैब्स के लिए गाइडलाइन भी जारी की हैं। अगर कोई फ्रेंचाइजी पांच खिलाड़ियों को रिटेन करती है, तो उसकी पर्स से 9.25 करोड़ रुपए काटे जाएंगे। चार खिलाड़ियों के लिए 8.75 करोड़ रुपए, तीन के लिए 7.75 करोड़ रुपए, दो के लिए 6 करोड़ रुपए और एक के लिए 3.5 करोड़ रुपए घटाए जाएंगे।

बज गया आईपीएल 2026 का बिगुल

● दिसंबर के दूसरे हफ्ते में नीलामी की संभावना, 15 नवंबर तक तय करनी होगी रिटेंशन लिस्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 की नीलामी दिसंबर 2025 के दूसरे या तीसरे हफ्ते में होने की संभावना है। अभी इसकी संभावित तारीखें 13 से 15 दिसंबर बताई जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार, फ्रेंचाइजी पदाधिकारियों ने बीसीसीआई से हुई बातचीत में इन तारीखों पर चर्चा की है। हालांकि, लीग की गवर्निंग काउंसिल ने अब तक शेड्यूल पर अंतिम फैसला नहीं लिया है।

इस बार नीलामी भारत में होने की उम्मीद

रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) इस बार नीलामी भारत में कराने के मूड में है। फ्रेंचाइजियों का भी यही मानना है कि मिनी ऑक्शन देश में ही हो। पिछले दो साल नीलामी विदेश (2023 में दुबई और 2024 में सऊदी अरब के जेद्दा) में हुई थी।

15 नवंबर तक तय करनी होगी रिटेंशन लिस्ट

फ्रेंचाइजियों के पास खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट सौंपने के लिए 15 नवंबर तक का समय है। इस तारीख तक हर टीम को बताना होगा कि किन खिलाड़ियों को रखना है और किन्हें रिलीज करना है। बड़े बदलाव की उम्मीद ज्यादा नहीं है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स ऐसी दो टीमें हैं जो पिछले सीजन के खराब प्रदर्शन के बाद बड़ा फेरबदल कर सकती हैं।

कैमरन ग्रीन हो सकते हैं सबसे हॉट खिलाड़ी

इस बार की नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन के सबसे चर्चित रहने की संभावना है। चोट की वजह से वह पिछली नीलामी से बाहर रहे थे, लेकिन इस बार कई टीमें उन्हें अपने पाले में लेने के लिए तैयार हैं।

दिसंबर 2025 में फिर बढ़ेगा रोमांच

आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी भले छोटी हो, लेकिन इसमें कई बड़े नामों की किस्मत बदल सकती है।

बीसीसीआई की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि दिसंबर का महीना फिर क्रिकेट फैंस के लिए रोमांच से भरा रहने वाला है।

IPL 2026 से पहले सीएसके में होगा बड़ा बदलाव, इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी पांच बार की चैम्पियन टीम

नई दिल्ली, एजेंसी। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. पांच बार की आईपीएल चैम्पियन टीम सीएसके ने 14 में से केवल 4 मुकाबले जीते थे और वो अंकतालिका में आखिरी स्थान पर रही थी. टीम मैनेजमेंट अब आईपीएल 2026 से पहले बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन से पहले पांच खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है. जिन खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया जा सकता है- उनमें सैम करन (इंग्लैंड), डेवोन कॉन्वे (न्यूजीलैंड), दीपक हुड्डा, विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी शामिल हैं. टीम के बेहद खराब प्रदर्शन के चलते इन खिलाड़ियों को रिलीज करने की नौबत आई है. आईपीएल 2025 में ऋतुराज गायकवाड़ की चोट ने भी चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलों में इजाफा किया था. ऋतुराज के बाहर होने के बाद एमएस धोनी ने टीम की कमान संभाली, लेकिन वो भी टीम की किस्मत नहीं बदल सके. अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा करने की रणनीति इस बार उलटी पड़ गई.

इस मामले में फिसड्डी रही सीएसके टॉप ऑर्डर के खराब प्रदर्शन ने चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें काफी बढ़ाईं. डेवोन कॉन्वे, दीपक हुड्डा, विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी का फॉर्म लगातार गिरता गया. आईपीएल 2025 में सीएसके के बल्लेबाजों ने 138.29 के स्ट्राइक रेट से 2315 रन बनाए, जो पिछले सीजन में किसी टीम का सबसे कम स्ट्राइक रेट था. इसके अलावा सीएसके ने पावरप्ले में सबसे कम रन (693) बनाए, साथ ही 29 विकेट गंवाए.

रणजी ट्रॉफी:

दिल्ली ने किया टीम का ऐलान, बडोनी करेंगे कप्तानी, नीतीश राणा की वापसी

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली ने हैदराबाद के खिलाफ 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच के लिए शुक्रवार को 24 सदस्यीय टीम की घोषणा की जिसमें आयुष बडोनी को कप्तान और यश ढुल को उपकप्तान नियुक्त किया गया है।

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ की चयन समिति ने नितीश राणा को भी टीम में शामिल किया है। राणा उत्तर प्रदेश के साथ कुछ समय तक खेलने के बाद दिल्ली की टीम में वापस आ गए हैं। DDCA सचिव अशोक शर्मा ने बताया, 'चयनकर्ताओं ने 24 खिलाड़ियों को इसलिए चुना है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे प्रत्येक मैच में चयन के लिए एक बड़ा पूल हमेशा उपलब्ध रहता है। जब हम दिल्ली में घरेलू मैच खेलेंगे, तो हम इसे घटाकर 15 कर देंगे। राणा की वापसी पर शर्मा ने कहा, 'वह एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और चयनकर्ता उन्हें परखना चाहते थे।

अगले मैच में हम ऋषभ पंत के खेलने की उम्मीद कर रहे हैं। बैठक में चयनकर्ता यशपाल सिंह, के भास्कर पिल्लई और मनु नायर के साथ-साथ मुख्य कोच सरनदीप सिंह, सीएसी सदस्य सुरिंदर खन्ना और डीडीसीए के अधिकारी अशोक शर्मा (सचिव) और अमित ग्रोवर (संयुक्त सचिव) भी शामिल हुए।

दिल्ली टीम:

आयुष बडोनी (कप्तान), यश ढुल (उप-कप्तान), अर्पित राणा, सनत सांगवान, अनुज रावत (विकेटकीपर), सुमित माथुर, शिवम शर्मा, रौनक वाघेला, नवदीप सैनी, सिमरजीत सिंह, मनी ग्रेवाल, सिद्धांत शर्मा, ध्रुव कौशिक, प्रणव राजवंशी (विकेटकीपर), नीतीश राणा, हिम्मत सिंह, आयुष दोसेजा, राहुल डागर, रितिक शौकीन, प्रियांश आर्य, तेजस्वी (विकेटकीपर), वैभव कांडपाल, रोहन राणा, आर्यन राणा (फिटनेस हासिल करने पर)।

महिला विश्व कप:

ऋचा घोष पर भारी पड़ी नादिन डी क्लर्क की पारी, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया

विशाखापत्तनम, एजेंसी। महिला विश्व कप 2025 के बेहद अहम मुकाबले में भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम द्वारा दिए 252 रन के लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने 48.5 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 252 का लक्ष्य हासिल करने उतरी दक्षिण अफ्रीका ने कप्तान लौरा वोल्वार्ट के 111 गेंद पर 70, नादिन डी क्लर्क के 54 गेंद पर नाबाद 84, और क्लो ट्रायोन के 66 गेंद पर 49 रन की पारी की मदद से 48.5 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 252 रन बनाकर मैच जीत लिया। दक्षिण अफ्रीका एक समय 142 पर 6 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी। इस समय मैच भारत की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा था। लेकिन ट्रायोन और क्लर्क ने सातवें विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी कर भारतीय टीम की जीत के मंसूबे पर पानी फेर दिया। क्लार्क ने 54 गेंद पर खेली 84 रन की नाबाद पारी में 5 छक्के और 8 चौके लगाए। इससे पहले एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 251 रन बनाए थे। भारतीय टीम को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने गंभीर शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 10.2 ओवर में 55 रन जोड़े। मंधाना 23 रन बनाकर आउट हुईं। प्रतिका भी 37 रन बनाकर आउट हुईं।

गाजा में युद्धविराम समझौता स्थानीय समय के अनुसार दोपहर से लागू : इजराइली सेना

» तेल अवीव, भाषा।

इजराइली सेना ने शुक्रवार को कहा कि गाजा पट्टी के लिए इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम समझौता स्थानीय समयानुसार दोपहर से लागू हो गया है और सैनिक सहमति वाले स्थान पर लौट रहे हैं। यह घोषणा इजराइल के मंत्रिमंडल द्वारा गाजा पट्टी में युद्धविराम, शेष बंधकों और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को मंजूरी देने के कुछ घंटों बाद आई। मध्य गाजा के वादी गाजा में सुबह-सुबह इकट्ठा हुए हज़ारों लोग स्थानीय समयानुसार दोपहर में सेना की घोषणा के बाद उत्तर की ओर चल पड़े। इससे पहले, फलस्तीनियों ने शुक्रवार सुबह पूरे गाजा में भारी गोलाबारी की सूचना दी थी। ट्रंप की योजना को इजराइली कैबिनेट द्वारा मंजूरी देना दो साल से जारी विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसने पश्चिम एशिया को अस्थिर कर रखा था। शुक्रवार तड़के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौते की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है।

हालांकि इसमें इस योजना के अन्य विवादास्पद पहलुओं का उल्लेख नहीं किया गया है। वापसी की संवेदनशीलता के कारण नाम गुप्त रखने की शर्त पर एक इजराइली सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि सेना अपनी नई स्थिति में गाजा के लगभग 50 प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण रखेगी। गोलाबारी तड़के तक जारी रही। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद गाजा निवासियों ने शुक्रवार सुबह तक गोलाबारी तेज होने की सूचना दी। मध्य गाजा के नुसेरात शरणार्थी शिविर में, गाजा शहर से विस्थापित होकर वहां शरण लिए कई लोगों में से एक, महमूद शार्कावी ने बताया कि तड़के

तोपखाने की गोलाबारी तेज हो गई। शार्कावी ने कहा, आज गोलाबारी में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि मध्य गाजा के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले सैन्य विमान भी उड़ रहे हैं। उत्तरी गाजा में लोगों ने बताया कि बमबारी तड़के से ही जारी थी। शिफा अस्पताल के प्रबंध निदेशक, रामी महन्ना ने कहा कि इजराइली कैबिनेट द्वारा युद्धविराम योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद भी दक्षिणी और उत्तरी गाजा शहर में गोलाबारी बंद नहीं हुई है। पूर्वी गाजा शहर में अपने घर के नष्ट हो जाने के बाद शहर के दूसरे इलाके में चली गई हेबा गरौन ने कहा, यह भ्रमित करने वाला है, युद्धविराम की ख़बरों के बावजूद हम पूरी रात गोलाबारी सुनते रहे। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी और प्रमुख वार्ताकार ने बृहस्पतिवार को एक संबोधन में युद्धविराम समझौते के मुख्य तत्वों को रेखांकित किया इजराइल लगभग 2,000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा।

ट्रंप की चतुर चाल या शायद गलतफहमी के कारण हुआ इजराइल-हमास युद्ध विराम समझौता

वाशिंगटन, भाषा। कई महीनों के गतिरोध के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक चतुर चाल या शायद एक गलतफहमी के कारण गाजा में इजराइल-हमास युद्ध विराम कुछ दिनों में समझौता हो गया और दोनों पक्ष इस पर राजी हो गए। बुधवार को घोषित इस समझौते के तहत अंतिम 48 बंधकों कि रिहाई तय हुई है, जिनमें से लगभग 20 के जीवित होने की संभावना है। अमेरिका के दो वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, समय के साथ हमास के लिए बंधक बोझ बन गए थे, जिससे समझौते का रास्ता खुला। एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर के नेतृत्व में वार्ताकारों ने पाया कि हमास अब थक चुका है। समझौते के बावजूद

प्रमुख प्रश्न अब भी बने हुए हैं, जिसमें शासन और उस क्षेत्र के पुनर्निर्माण के सवाल शामिल है जो काफी हद तक नष्ट हो गया है। साथ ही यह भी सवाल है कि क्या हमास निरस्त्रीकरण करेगा, जो इजराइल की प्रमुख मांग है और जिसे हमास ने अभी तक सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। सितंबर की शुरुआत में जब अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता वाली शांति वार्ताएं ठप पड़ी थीं तो इजराइल ने कतर में हमास नेताओं पर हवाई हमला किया, जिससे पांच हमास सदस्यों और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी की मौत हुई। इस घटना से खाड़ी देशों और अमेरिका में भारी नाराजगी फैल गई। ट्रंप ने तुरंत कतर से माफी मांगी क्योंकि यह हमला पश्चिम एशिया में शांति के उनके अभियान को नुकसान पहुंचा सकता था। दो सप्ताह बाद ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान आठ मुस्लिम देशों के नेताओं से मुलाकात की और अपनी 20 सूत्रीय शांति योजना प्रस्तुत की। योजना में हमास से सभी बंधकों की रिहाई, हथियार छोड़ने और सत्ता छोड़ने की मांग की गई थी। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर यह अंतिम मौका असफल रहा, तो हमास पर ऐसा प्रहार होगा जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। कुछ घंटों बाद हमास ने जवाब, हां, लेकिन...। अमेरिका और इजराइल इसे ना मान सकते थे और इज़राइल की शर्तों पर युद्धविराम न हो पाने के लिए हमास को दोषी ठहरा सकते थे, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया था। इज़राइल गाजा शहर पर आक्रमण जारी रखने की कसम भी खा सकता था। लेकिन जब शुक्रवार देर रात हमास की प्रतिक्रिया आई, तो ट्रंप ने इसे शांति समझौते के लिए हमास की स्वीकृति माना और तुरंत गाजा पर बमबारी रोकने की अपील की। इजराइल ने भी बंधकों की रिहाई के पहले चरण की तैयारी की घोषणा की।

इजराइल के मंत्रिमंडल ने बंधकों की रिहाई के लिए समझौते की रुपरेखा को मंजूरी दी

काहिरा, भाषा। इजराइल के मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम और हमास द्वारा सभी शेष बंधकों की रिहाई की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। यह पश्चिम एशिया को अस्थिर करने वाले दो साल के विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से जारी एक संक्षिप्त बयान में बताया गया कि मंत्रिमंडल ने बंधकों की रिहाई के लिए समझौते की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है, हालांकि इसमें योजना के उन अन्य पहलुओं का उल्लेख नहीं किया गया है जो अधिक विवादास्पद हैं। व्यापक युद्धविराम योजना में कई ऐसे प्रश्न शामिल हैं जिनके उत्तर नहीं मिले हैं जैसे कि हमास निरस्त्रीकरण करेगा या नहीं और यदि करेगा तो कैसे करेगा तथा गाजा पर शासन कौन करेगा। बहरहाल, दोनों पक्ष पिछले कुछ महीनों की तुलना में उस युद्ध को समाप्त करने के करीब दिखाई दिए जिसमें हजारों फलस्तीनी मारे गए, गाजा का अधिकतर हिस्सा मलबे में बदल गया और क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अकाल की स्थिति पैदा हो गई। इस बीच, अमेरिकी अधिकारियों ने घोषणा की कि वे एक व्यापक एवं अंतरराष्ट्रीय टीम के हिस्से के रूप में युद्धविराम समझौते का समर्थन और निगरानी करने के लिए इजराइल में लगभग 200 सैनिक भेजेंगे। अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यूएस सेंट्रल कमांड इजराइल में एक असैन्य-सैन्य समन्वय केंद्र स्थापित करेगा जो दो साल से युद्ध से त्रस्त क्षेत्र में मानवीय सहायता के साथ-साथ रसद और सुरक्षा सहायता के प्रवाह को सुगम बनाने में मदद करेगा। युद्ध की शुरुआत सात अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले से हुई जिसमें लगभग।,200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इजराइल के जवाबी सैन्य हमले में हजारों फलस्तीनी मारे गए, गाजा तबाह हो गया और वैश्विक राजनीति में उथल-पुथल मच गई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, गाजा में 67,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं और लगभग 170,000 घायल हुए हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से यह तीसरा युद्धविराम होगा। पहला युद्धविराम नवंबर 2023 में हुआ था जिसमें 100 से अधिक बंधकों को फलस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया गया था लेकिन युद्धविराम समझौता टिक नहीं पाया।

गोंजालेज ने मारिया को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर खुशी जाहिर की

वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा

» ओस्लो, भाषा।

वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की शुक्रवार को घोषणा की गई। मारिया को एक ऐसी महिला के रूप में मान्यता दी गई है, जिन्होंने गहराते अंधकार के बीच लोकतंत्र की लौ जलाए रखी है। नॉर्वे की नोबेल समिति के अध्यक्ष जॉर्गन वाले फ्रिडनेस ने कहा कि वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विपक्ष की उम्मीदवार रहीं मारिया को राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार के खिलाफ कभी गहरे तक विभाजित विपक्ष को एकजुट करने वाली महत्वपूर्ण शख्सियत के रूप में सराहा गया है। फ्रिडनेस ने कहा, मारिया पिछले एक साल से छिपकर रहने के लिए मजबूर हैं। जान को गंभीर खतरे के बावजूद वह देश में ही हैं और इस फैसले ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा, जब अधिनायकवादी सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं, तो आजादी की रक्षा करने वाले उन साहसी नायकों को मान्यता देना अहम हो जाता है, जो आवाज उठाते हैं और प्रतिरोध करते हैं। फ्रिडनेस ने समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस से कहा कि समिति घोषणा से कुछ देर पहले मारिया से संपर्क करने में सफल रही थी, जिन्होंने इस पुरस्कार के लिए चुने जाने पर विस्मय व्यक्त किया।

मारिया के करीबी सहयोगी एडमंडो गोंजालेज (जो स्पेन में निर्वासन में रह रहे हैं) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह फोन पर उनसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में मारिया को गोंजालेज से यह कहते हुए सुना जा सकता है, मैं आश्चर्यचकित हूं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। गोंजालेज ने मारिया को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के फैसले पर खुशी जाहिर की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह हमारी आजादी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक महिला और लोगों की लंबी लड़ाई को मिली बहुत ही उपयुक्त मान्यता है। इस हफ्ते अपना 58वां जन्मदिन मनाने वाली

मारिया को राष्ट्रपति चुनाव में मादुरो के खिलाफ लडना था, लेकिन सरकार ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। इसके बाद गोंजालेज को राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया। यह उनके जीवन का पहला चुनाव था। चुनावी प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर दमन देखा गया, जिसमें विरोधी उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया जाना, उनकी गिरफ्तारी और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन शामिल था। विरोधियों का दमन तब और बढ़ गया, जब मादुरो के वफादारों से भरी देश की राष्ट्रीय चुनाव परिषद ने चुनावी शुचिता से समझौते के विश्वसनीय सबूतों के बावजूद उन्हें (मादुरो को) विजेता घोषित कर दिया। चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद देशभर में विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर बल प्रयोग किया गया, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। इस घटनाक्रम के बाद वेनेजुएला के अर्जेंटीना सहित विभिन्न देशों के साथ राजनयिक संबंध समाप्त हो गए। मारिया अज्ञात स्थान पर चली गईं और उन्हें जनवरी से किसी सार्वजनिक मंच पर नहीं देखा गया है। वेनेजुएला की एक अदालत ने चुनाव नतीजों के प्रकाशन को लेकर गोंजालेज के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इसके बाद वह स्पेन में निर्वासन में चले गए, जहां उन्हें शरण मिल गई। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में लोगों ने मारिया के नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की खबर पर विस्मय व्यक्त किया।

नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप की कोशिशें नाकाम रहीं

वाशिंगटन, भाषा। प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। रिपब्लिकन नेताओं से लेकर दुनिया के कई नेताओं द्वारा ट्रंप को यह पुरस्कार दिए जाने की वकालत किए जाने और खुद ट्रंप द्वारा उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार का उचित उम्मीदवार बताए जाने के बावजूद वह इसे पाने से चूक गए। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नॉर्वे की नोबेल समिति के अध्यक्ष जॉर्गन वाले फ्रिडनेस ने कहा कि वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद की विपक्ष की उम्मीदवार रहीं मारिया कोरिना मचाडो कभी गहन तौर पर विभाजित रहे विपक्ष को एकजुट करने वाली प्रमुख शख्सियत हैं। एक ऐसा विपक्ष जिसने स्वतंत्र चुनाव और प्रतिनिधि सरकार की मांग को समान रूप से उठाया। मौजूदा कार्यकाल के अलावा ट्रंप अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने के लिए सार्वजनिक तौर पर अपनी मंशा जताते रहे हैं। खासकर हाल में, जब उन्होंने दुनिया भर में संघर्षों को समाप्त करने का श्रेय लेते हुए इस सम्मान को पाने की अपनी इच्छा के बारे में खुलकर कहा था। हालांकि, उन्होंने संदेह व्यक्त किया था कि नोबेल समिति उन्हें कभी यह पुरस्कार देगी।ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार क्यों मिलना चाहिए इसके लिए वह कई कारण बताते हैं। इनमें से एक कारण वी यह भी कई बार बता चुके हैं कि उन्होंने सात युद्ध समाप्त कराए हैं। ट्रंप ने बृहस्पतिवार को कहा था, वे वही करेंगे, जो उन्हें करना है। वे जो भी करें, ठीक है। मैं यह जानता हूं कि मैंने यह (संघर्ष समाप्त करवाना) किसी और चीज के लिए नहीं किया। मैंने यह बहुत से लोगों की जान बचाने के लिए किया है। तीन अमेरिकी राष्ट्रपतियों को पद पर रहते हुए नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, जिनमें थियोडोर रूजवेल्ट को 1906 में, वुडरो विल्सन को 1919 में और बराक ओबामा को 2009 में ए पुरस्कार मिला था। जिमी कार्टर ने पद छोड़ने के पूरे दो दशक बाद 2002 में यह पुरस्कार जीता था। पूर्व उप राष्ट्रपति अल गोर को 2007 में यह पुरस्कार मिला था।

न्यूज ब्रीफ

रूस के हवाई हमलों में यूक्रेन की राजधानी में भारी नुकसान, कम से कम 20 लोग घायल

» कीव, भाषा।

रूस द्वारा शुक्रवार तड़के यूक्रेन में ड्रोन और मिसाइल से किए गए हवाई हमलों में कीव में कम से कम 20 लोग घायल हो गए, आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचा और देश के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। देश के दक्षिण पूर्व में अलग से हुए हमलों में एक बच्चे की भी मौत हो गई। यूक्रेन की राजधानी के बीचोंबीच स्थित 17 मंजिला एक इमारत से बचाव दल ने 20 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला। इस इमारत की छठी और सातवीं मंजिल पर आग की लपटें फैल गई थीं। अधिकारियों ने बताया कि पांच लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य को घटनास्थल पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। रात भर चला यह हमला कीव पर हमलों की कड़ी में नवीनतम है।

राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर कहा कि रूसी हमलों ने नागरिक और ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाया, जहां यूक्रेन सर्दियों के लिए तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री यूलिया स्विरीदेन्को ने भी इस हमले को यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे के खिलाफ सबसे बड़े केंद्रित हमलों में से एक बताया। कीव के मेयर विताली क्लित्स्को ने कहा कि शुक्रवार के हमले से शहर के दोनों ओर बिजली गुल हो गई और पानी की आपूर्ति बाधित हो गई। यूक्रेन की वायु सेना ने शुक्रवार को कहा कि रूस के ताजा हमले में 465 हमलावर और झांसा देने वाले ड्रोन, साथ ही विभिन्न प्रकार की 32 मिसाइलें शामिल थीं। वायु रक्षा बलों ने 405 ड्रोन और 15 मिसाइलों को रोका या जाम कर दिया। सैन्य प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी जापोरिज्जिया क्षेत्र में, आवासीय क्षेत्रों और ऊर्जा संयंत्रों पर हमलावर ड्रोन, मिसाइलों और बमों से हमला किया गया।

फिलीपीन में भूकंप का दूसरा शक्तिशाली झटका, पहले में पांच व्यक्तियों की मौत

» मनीला, भाषा।

दक्षिणी फिलीपीन के पास एक ही क्षेत्र में कुछ घंटों के अंतराल पर शुक्रवार को दो शक्तिशाली भूकंप आए। भूकंप का पहला झटका सुबह में महसूस किया गया जिसकी तीव्रता 7.4 मापी गई। इसमें कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई। वहीं, इससे भूस्खलन हुआ, अस्पतालों और विद्यालयों को नुकसान पहुंचा और सुनामी की चेतावनी के कारण आसपास के तटीय क्षेत्रों को खाली कराना पड़ा। हालांकि, सुनामी की चेतावनी बाद में वापस ले ली गई। दूसरे भूकंप की प्रारंभिक तीव्रता 6.9 थी। फिलीपीन के ज्वालामुखी विज्ञान और भूकंप विज्ञान संस्थान के प्रमुख टेरेसिटो बैकोलकोल ने बताया कि शुक्रवार को आए भूकंप के झटके दावाओ ओरिएंटल प्रांत के मनय शहर में महसूस किए गए थे। यह भूकंप फिलीपीन ट्रेंच में 10 किलोमीटर की गहराई पर हुई हलचल के कारण आया था।

यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह एक अलग भूकंप था या 7.4 तीव्रता वाले भूकंप का ही एक और झटका था। फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कहा कि भूकंप के बाद संभावित क्षति का आकलन किया जा रहा है तथा सुरक्षित स्थिति होने पर बचाव एवं राहत अभियान शुरू किया जाएगा। पहले भूकंप का केंद्र दावाओ ओरिएंटल प्रांत के मनाय शहर से

लगभग 43 किलोमीटर पूर्व में पास समुद्र में स्थित था। सरकार के नागरिक सुरक्षा कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक एडनार दयांगिरांग ने टेलीफोन पर एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि कम से कम पांच लोग मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि मारे गए लोगों में दो मरीज भी शामिल हैं, जिनकी भूकंप के दौरान अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उन्होंने बताया कि साथ ही एक निवासी की दावाओ ओरिएंटल के माटी शहर में मलबे की चपेट में आने से मौत हो गई। दयांगिरांग ने बताया कि दावाओ ओरिएंटल के निकट दावाओ डी ओरो प्रांत के पंतुकन कस्बे के एक सुदूर सोने की खदान वाले गांव में भूकंप के कारण हुए भूस्खलन में दो ग्रामीणों की मौत हो गई तथा कई अन्य को सेना और नागरिक स्वयंसेवकों ने बचा लिया, हालांकि वे घायल हो गए। नागरिक सुरक्षा कार्यालय के उप प्रशासक बर्नार्डो राफेलिटो एलेजांद्रो चतुर्थ ने बताया कि कई इमारतों की दीवारों में दरारें आ गईं, जिनमें दावाओ शहर का एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हालांकि, हवाई अड्डे पर उड़ानों का संचालन जारी है और कोई उड़ान रद्द नहीं की गई है। दावाओ ओरिएंटल के गवर्नर जेनेरोसो कस्बे के आपदा न्यूनीकरण अधिकारी जून सावेद्रा ने मोबाइल पर एसोसिएटेड प्रेस को बताया, मैं अपनी कार चला रहा था, तभी मेरी कार डगमगाने लगी और मैंने बिजली के तारों को बेतरतीब ढंग से हिलते देखा। जमीन हिलने और बिजली गुल होने पर लोग घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। सावेद्रा ने कहा, हमारे यहां पहले भी भूकंप आए हैं, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली था। उन्होंने बताया कि जमीन के तीव्र कंपन के कारण कई इमारतों में दरारें पड़ गईं, जिनमें एक हाई स्कूल भी शामिल है, जहां पहले भूकंप के कारण चोट लगने, बेहोश होने या चक्कर आने के बाद लगभग 50 छात्रों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल लाया गया था। गवर्नर जेनेरोसो, माने से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक कस्बा है, जहां सभी स्तरों पर स्कूल कक्षाएं भी स्थगित कर दी गई। दावाओ शहर में बच्चों ने स्कूल खाली कर दिए, जहां लगभग 54 लाख लोग रहते हैं और यह भूकंप के केंद्र के पास सबसे बड़ा शहर है। होनोलूलू स्थित प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा कि पहले भूकंप के लगभग दो घंटे बाद खतरा टलने से पहले फिलीपीन और इंडोनेशिया के तटों पर छोटी लहरें देखी गईं। इसने कहा कि समुद्र में छोटे-छोटे उतार-चढ़ाव जारी रह सकते हैं। मुख्य सरकारी भूकंप विज्ञानी टेरेसिटो बैकोलकोल ने कहा कि सुनामी की चेतावनी, बाद में बिना किसी बड़ी लहर का पता चले वापस ले ली गई। इस चेतावनी के कारण दावाओ ओरिएंटल के पास तटीय प्रांतों से लोगों को निकाला गया था।

पाकिस्तानी लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते रहेंगे: सेना

» पेशावर, भाषा।

पाकिस्तान ने शुक्रवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर हुए हमलों में अपने सुरक्षा बलों की संलिप्तता की पुष्टि या खंडन करने से इनकार कर दिया और कहा कि अपने लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते रहेंगे। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान ने अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और पक्तिका प्रांत में एक नागरिक बाजार पर बमबारी की, तथा काबुल के हवाई क्षेत्र का भी उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से यहां एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान दो बार पूछा गया कि क्या पाकिस्तानी सेना ने काबुल में हवाई हमले किए हैं, जहां बृहस्पतिवार रात 10 बजे से पहले कई मंत्रालयों के नजदीक एक चौक पर धमाका हुआ था।

पहली बार इस सवाल के जवाब में लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने बिना इसकी पुष्टि या खंडन किए कहा,आपने हमले के बारे में जो कहा, वह मीडिया और सोशल मीडिया तथा अफगान (तालिबान सरकार) प्रवक्ता के बयान में दर्ज है। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। पाकिस्तान ने चार दशकों से भी ज़्यादा समय से लाखों अफगान शरणार्थियों की मेजबानी की है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने कहा, हम अफगान सरकार से मांग करते हैं कि आप अपनी ज़मीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होने दें।

नए प्रधानमंत्री को तुरंत अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से बचने के लिए कुछ समझौते करने पड़ेंगे

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नए प्रधानमंत्री की करने वाले हैं घोषणा

» पेरिस, भाषा।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों एक हफ्ते की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद शुक्रवार को नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। इसे आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे देश में एक साल से अधिक समय से जारी सियासी गतिरोध को हल करने की उनकी एक और कोशिश माना जा रहा है। नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति को मैक्रों के लिए अपने दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में जान फूंकने के आखिरी मौके के तौर पर भी देखा जा रहा है, जो 2027 में समाप्त होने वाला है। मैक्रों के पास अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल असेंबली (फ्रांसीसी संसद का निचला सदन) में बहुमत नहीं है।

इसके अलावा, उन्हें न सिर्फ विपक्ष की, बल्कि अपने ही खेमे के सदस्यों की भी तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। निवर्तमान प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु ने सोमवार को नए मंत्रिमंडल की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद अचानक इस्तीफा दे दिया। इस घटनाक्रम के चलते मैक्रों पर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने या नेशनल असेंबली को भंग करने का दबाव फिर से तेज होने लगा। हालांकि, उन्होंने ऐसा कोई भी कदम उठाने से एक बार फिर इनकार करते हुए बुधवार को घोषणा की कि वह अगले 48 घंटे में लेकोर्नु के उत्तराधिकारी की घोषणा कर देंगे। पिछले साल मैक्रों के नेतृत्व वाली अल्पमत सरकार को लगातार अस्तित्व के संकट से जूझना पड़ा है, जिससे यूरोपीय संघ की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रांस राजनीतिक गतिरोध

में उलझकर रह गई है और उस पर ऋण संकट गहराता जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के अंत में फ्रांस का सार्वजनिक ऋण 33.46 खरब यूरो (लगभग 39 खरब अमेरिकी डॉलर) था, जो उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 114 फीसदी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, फ्रांस में गरीबी दर भी 2023 में 15.4 फीसदी तक पहुंच गई, जो 1996 में दस्तावेजीकरण शुरू होने के बाद से सर्वाधिक है। मैक्रों नए प्रधानमंत्री के रूप में किसी वामपंथी नेता को चुन सकते हैं, जिन्होंने 2024 के चुनावों में गठबंधन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी या फिर वह राजनीतिक गतिरोध से बचने के लिए किसी सर्वस्वीकार्य चेहरे पर मुहर लगा सकते हैं। बहरहाल, नए प्रधानमंत्री को तुरंत अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से बचने के लिए कुछ समझौते करने पड़ेंगे और यहां तक कि उन्हें पेंशन सुधार की योजना टालने के लिए भी मजबूर होना पड़ सकता है, जिसके तहत सेवानिवृत्ति की आयु को धीरे-धीरे 62 से बढ़ाकर 64 साल किए जाने का प्रावधान है। मैक्रों ने भारी विरोध के बावजूद 2023 में इस प्रस्ताव को कानून का रूप देने पर मुहर लगाई थी। लेकोर्नु ने कहा कि मैक्रों का मध्यमार्गी गुट, उसके सहयोगी और कुछ विपक्षी दल अभी भी एकजुट होकर बहुमत की सरकार बना सकते हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अभी भी संभावना है। हालांकि, यह थोड़ा मुश्किल है। फ्रांस में राजनीतिक गतिरोध जून 2024 में शुरू हुआ था, जब मैक्रों ने सभी को चौंकाते हुए नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की थी। इसके बाद आनन-फानन में हुए चुनावों में कोई भी पार्टी 577 सीटों वाली नेशनल असेंबली में बहुमत नहीं हासिल कर सकी थी।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत में एआई और फिनटेक निवेश के साथ अपनी यात्रा का समापन किया

» लंदन, भाषा।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने कहा है कि उन्होंने अपनी भारत यात्रा के दौरान हजारों नौकरियों के अवसर सुनिश्चित किए, जिसमें ब्रिटेन की कई कंपनियों ने एआई और फिनटेक क्षेत्रों में 3.6 अरब पाउंड के निवेश की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ व्यापक वार्ता के बाद बृहस्पतिवार को अपनी मुंबई यात्रा संपन्न करने वाले स्टार्मर ने कहा कि इस यात्रा से ब्रिटेन को जुलाई में हस्ताक्षरित व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौते (सीईटीए) द्वारा उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिली है। उन्होंने महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत में ब्रिटेन के व्यवसायों के लिए और अधिक अवसर की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समझौते से शुल्क (टैरिफ) कम हो जाएंगे और व्यापार तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा।

स्टार्मर ने अपनी भारत यात्रा के समापन पर एक बयान में कहा, 125 सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ, हमने इस सप्ताह भारत के साथ अपने व्यापार समझौते से उत्पन्न अवसरों का पूरा लाभ उठाया है। उन्होंने कहा, हमने ब्रिटेन में नए निवेश हासिल किए हैं और पूरे देश में, हमारे

कुछ सबसे फलते-फूलते उद्योगों में 10,600 नौकरियां के अवसर पैदा होंगे। हमने भारत में ब्रिटेन के व्यवसाय के लिए नए द्वार खोले हैं और साझेदारियों को मज़बूत किया है। हमारा दूरदर्शी और गौरवपूर्ण दृष्टिकोण वास्तविक बदलाव ला रहा है, जिसे लोग देश भर में अपने समुदायों में देखेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ने रेखांकित किया कि ब्रिटेन की कंपनियों द्वारा किए गए कुछ प्रमुख निवेशों में सॉफ्टबैंक समूह का हिस्सा ग्राफकोर भी शामिल है, जो बेंगलुरु में एक नए एआई इंजीनियरिंग परिसर में एक अरब पाउंड तक का निवेश करेगा, जिससे भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग में 500 उच्च कौशल वाली नौकरियां पैदा होंगी।

मुद्रक, प्रकाशक व स्वत्त्वाधिकारी मुन्ना खान के लिए श्री राम ऑफसेट, 6, शॉपिंग सेंटर, जोरावर सिंह गेट के बाहर, आमेर रोड, जयपुर से मुद्रित तथा रॉयल पत्रिका कार्यालय 4312 मोहल्ला नायकों का, जगन्नाथ शाह का रास्ता, नाहरबाड़ा, रामगंज, जयपुर से प्रकाशित। संपादक मुन्ना खान मों. 08058969180 कार्यालय फोन- 0141-2609886,